सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 12 अगस्त, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 333, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून पर क्यों उठ रहे सवाल ?

उमंग पोद्दार

साल 2023 में भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया। यह क़ानून नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मक़सद से लाया गया था। कई मसौदों पर विचार के बाद अगस्त 2023 में यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ और इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली। हालांकि, क़ानून के बनने के बाद से ही इसकी आलोचना हो रही है। आलोचकों में पत्रकार भी शामिल हैं, जिनका मानना है कि इस क़ानून से पत्रकारिता की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

बीते 28 जुलाई को कई पत्रकार संगठनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव एस कृष्णन से मुलाक़ात की। इस बैठक में उन्होंने सरकार से क़ानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन की मांग की। फ़िलहाल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। इस क़ानून में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिन पर केंद्र सरकार को नियम बनाने होंगे। जनवरी 2025 में सरकार ने इस क़ानून से संबंधित ड्राफ्ट रूल्स जारी किए थे, जिन पर अभी विचार किया जा रहा है।

साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था, जिसके बाद यह क़ानून लाया गया। इस क़ानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी के व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल करता है, तो उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा। मिसाल के तौर पर किसी का भी निजी डेटा लेने से पहले उस व्यक्ति से सहमति लेनी होगी, डेटा का इस्तेमाल वैध मक़सद के लिए करना होगा और साथ ही डेटा की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। इसके मुताबिक़, कोई व्यक्ति अपना निजी डेटा देने के बाद उसे हटवाने की भी माँग कर सकता है। इस क़ानून का उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सरकार इस जुर्माने को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक भी कर सकती है।

निजी डेटा में वह सारी जानकारी शामिल है जिससे किसी की पहचान सार्वजनिक हो सकती है। इसमें नाम, पता, फ़ोन नंबर, तस्वीर, सेहत और वित्तीय मामलों से जुड़ी जानकारी और किसी व्यक्ति की इंटरनेट ब्राउज़िंग हिस्ट्री जैसे विवरण शामिल हैं। साथ ही, इस क़ानून में डेटा को 'प्रोसेस' करने की भी परिभाषा दी गई है। इसमें डेटा इकट्ठा करना, उसे स्टोर करना और प्रकाशित करना शामिल है। इस क़ानून को लागू करने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की संस्था 'डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ़ इंडिया' की होगी। यह बोर्ड जुर्माना लगाने, शिकायतों पर सुनवाई करने जैसे कई मामलों में काम करेगा।

पत्रकार संगठनों का कहना है कि निजी डेटा का इस्तेमाल लगभग हर तरह की पत्रकारिता में होता है। अगर कोई पत्रकार किसी अफ़सर के भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट कर रहा है, तो उसमें उस अफ़सर के निजी डेटा का ज़िक्र आ सकता है। इसलिए पत्रकारों ने इस क़ानून के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। जैसे कि इस क़ानून के तहत सरकार कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का डेटा साझा करने का आदेश दे सकती है। पत्रकारों को आशंका है कि अगर सरकार इस तरह का आदेश जारी करती है, तो उनके गुप्त सूत्रों की पहचान उजागर हो सकती है। कई बार रिपोर्टिंग में ऐसे स्रोत शामिल होते हैं जिनकी गोपनीयता बनाए रखना ज़रूरी होता है।

फ़रवरी 2024 में 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया' ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखकर इस क़ानून के कई प्रावधानों पर चिंता जताई थी। गिल्ड ने लिखा था कि यह क़ानून 'पत्रकारिता के अस्तित्व के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है।' पत्रकारों का कहना था कि इस क़ानून से इंटरव्यू और दूसरी चीज़ें प्रभावित न भी हों लेकिन खोजी पत्रकारिता और संवेदनशील रिपोर्टिंग पर इसका असर पड़ सकता है। 25 जून को 22 प्रेस संगठनों और एक हज़ार से ज़्यादा पत्रकारों ने भी सरकार को ज्ञापन भेजा, जिसमें क़ानून में बदलाव की माँग की गई। इन पत्रकारों में अख़बार, टीवी, यूट्यूब और फ्रीलांसर पत्रकार शामिल हैं।

पत्रकारों की माँग है कि पत्रकारिता के कार्यों के लिए इस क़ानून से छूट दी जानी चाहिए। वर्तमान में कुछ उद्देश्यों, जैसे अपराध की जाँच के लिए डेटा प्रोटेक्शन क़ानून से छूट दी गई है। जब इस क़ानून का पहला ड्राफ्ट साल 2018 में प्रकाशित हुआ था, तब उसमें पत्रकारिता से संबंधित कई प्रावधानों से छूट दी गई थी। इसी तरह साल 2021 के ड्राफ्ट बिल में भी पत्रकारिता के लिए कुछ छूट थी। हालांकि, साल 2023 में जब यह क़ानून पारित किया गया, तो पत्रकारिता से जुड़ी छूट हटा दी गई। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया। पत्रकार संगठनों का कहना है कि 'पत्रकार की परिभाषा' को केवल मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोगों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ने अपनी चिट्ठी में यह भी उल्लेख किया है कि यूरोप और सिंगापुर जैसे देशों के डेटा प्रोटेक्शन क़ानूनों में पत्रकारिता को छूट दी गई है।

30 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया की उपाध्यक्ष, पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोती ने बताया कि उन्होंने 28 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव से मुलाक़ात की थी। उनके अनुसार, 'सरकार की ओर से कहा गया है कि इस क़ानून से पत्रकारों को कोई मुश्किल नहीं होगी। मंत्रालय के सचिव ने हमें एफ़एक्यूज़ (फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स) तैयार करके देने को कहा है।'

सूचना का अधिकार क़ानून (आरटीआई एक्ट) में प्रावधान है कि इसके तहत कोई निजी जानकारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर सार्वजनिक हित से जुड़ा मसला हो या अगर किसी व्यक्ति की निजता को ग़लत तरीके से पेश नहीं कर रहा हो तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन क़ानून में संशोधन के बाद यह प्रावधान बस इतना कहता है कि किसी की निजी जानकारी आरटीआई क़ानून के तहत सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

सरकार का तर्क है कि यह क़ानून सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है, जिनमें 'निजता' को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन क़ानून से सूचना के अधिकार (आरटीआई) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उनके अनुसार, अगर कोई जानकारी जनता के हित में है, तो वह पहले की तरह ही साझा की जाती रहेगी। हालांकि, पत्रकार संगठनों की क़ानून में बदलाव की माँग अब भी जारी है। उनका कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

भोपाल में पर्यावरण से समन्वय विषय पर कार्यशाला

विकास और पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं में सामंजस्य आवश्यक : सीएम यादव

संरचनात्मक प्रगति के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो : मंत्री श्री राकेश सिंह

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित हो, जिससे विकास के साथ प्रकृति भी संरक्षित रहें। भारत की प्राचीन निर्माण परंपराएं आज भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने भोपाल के बड़े तालाब का उदाहरण देते हुए बताया कि यह बिना किसी नदी की मुख्यधारा को रोके, प्राकृतिक चट्टानों के बीच पानी संग्रहित करने की तकनीक से बना था। यह तालाब केवल सजावट की वस्तु नहीं, बल्कि पीने के पानी का स्रोत भी है। इसकी संरचना इस तरह है कि अतिरिक्त पानी स्वतः बाहर निकल जाता है और संरचना की लागत भी कम रहती है। आज सड़क निर्माण में वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पुलों के नीचे अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जिससे बाघ और अन्य जानवर सुरक्षित रूप से गुजर सकें और यातायात भी प्रभावित न हो। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन की मिसाल है। वर्तमान समय में निर्माण सामग्री की मात्रा, डिज़ाइन की गुणवत्ता और लागत-प्रभावशीलता पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्माण में मात्रा से ज्यादा महत्व गुणवत्ता का है। अभियंता वह है जो विज्ञान, गणित और तकनीक, इन तीनों में समान दक्षता रखते हुए उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करे।

ऐसे निर्माण करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हों

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमें ऐसे निर्माण करने चाहिए, जिन पर हमें स्वयं गर्व हो और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हों। विभागीय दायरे और नियमों के भीतर रहते हुए भी अभियंताओं को रचनात्मक सोच से समाधान खोजने होंगे।

सड़क के गड्ढों की मरम्मत की समय-सीमा 7 दिन से घटाकर 4 दिन की जाएगी

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के अभियंताओं को अन्य राज्यों में भेजकर बेहतर तकनीकों का अध्ययन कराया गया। विभाग ने उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त बिटुमिन केवल सरकारी रिफाइनरियों से ही खरीदने का निर्णय लिया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि लोकपथ मोबाइल ऐप के माध्यम से सड़क मरम्मत व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। पहले गड्ढों की मरम्मत की समय-सीमा 7 दिन थी, जिसे हम शीघ्र ही घटाकर 4 दिन करने का निर्णय कर रहे हैं। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विभाग ने कई ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं।

विकास की गाड़ी कभी भी पर्यावरण की पटरी से नहीं उतरेगी

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि संभवतः यह पहली बार है जब मध्यप्रदेश के सभी अभियंता प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से एक साथ जुड़े हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विशेष रूप से आभार मानते हुए कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में विकास की गाड़ी कभी भी पर्यावरण की पटरी से नहीं उतरेगी। श्री सिंह ने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ तभी है जब संरचनात्मक प्रगति के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित हो। हमारे पूर्वजों ने संरचनाओं का संरक्षण इस प्रकार किया कि आने वाली पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिला। उन्होंने उदाहरण दिया कि त्रिची के पास 2000 वर्ष पुराना अनय कट्टू बांध आज भी कार्यरत है, जो भारतीय अभियंताओं की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। इसी तरह मोहन जोदाड़ो से प्राप्त 7000 वर्ष पुरानी ईंटों का उपयोग अंग्रेजों के समय रेल पटरियों के नीचे आधार के रूप में किया गया और वे कई दशकों तक मजबूती से टिकी रहीं। उन्होंने कहा कि यह परंपरा, यह कौशल और यह दृष्टि हमारे संस्कारों में है, जिसे वर्तमान में और भी मजबूत करना होगा।

मतदाता सूची संशोधन के विरोध में विपक्षी सांसदों का मार्च

बैरिकेड कूदकर अखिलेश का धरना; हिरासत में लिए गए राहुल-प्रियंका समेत कई सांसद; बाद में छोड़े गए

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए परिवहन भवन में पुलिस बैरिकेड्स लगा दिए। यहां उन्हें चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर आगे बढ़ने से रोक दिया गया। पुलिस का कहना था कि विपक्षी सांसदों की ओर से इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा समेत कई सांसदों ने बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की। कुछ सांसद बैरिकेड्स कूदकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सांसदों ने सड़क से हटने से इनकार किया तो राहुल-प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।

मल्लिकार्जुन खरगे और शरद पवार समेत विपक्षी सांसदों ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला। हालांकि, पुलिस ने उन्हें परिवहन भवन के पास बीच रास्ते में ही रोक दिया। मार्च में शामिल होने वालों में प्रमुख रूप से टीआर बालू (द्रमुक), संजय राउत (शिवसेना-यूबीटी), डेरेक ओब्रायन (टीएमसी), कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत द्रमुक, राजद और वामपंथी दलों जैसे विपक्षी दलों के अन्य सांसद शामिल थे।

दरअसल, चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को पत्र लिखकर दोपहर 12.30 बजे मिलने के लिए बुलाया था।

जयराम : चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, चुनाव आयोग को लिखा मेरा पत्र सीधा था। मैंने साफ-साफ लिखा था कि सभी विपक्षी सांसद संसद से चुनाव आयोग तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। सभी सांसद चुनाव आयोग को एसआईआर के बारे में एक दस्तावेज देना चाहते हैं। यही हमारी मांग थी। मैंने कल शाम यह पत्र लिखा था और 'चुनाव आयोग', जो अब 'चुराओ आयोग' बन गया है, ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया।

प्रियंका गांधी वाड्रा : कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने हिम्मत की है। सरकार डरी हुई है। सरकार कायर है।

ये लड़ाई संविधान बचाने की है : राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हकीकत ये है कि वो बात नहीं कर सकते। सच्चाई देश के सामने है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये लड़ाई एक व्यक्ति, एक वोट की है। हम एक साफ-सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं। राहुल ने कहा, भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलकर एक दस्तावेज पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। वे डरे हुए हैं। अगर 300 सांसद आ गए और उनकी सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? यह लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रही। यह लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के लिए है। हमने कर्नाटक में साफ तौर पर दिखा दिया है, यह मल्टीपल मैन, मल्टीपल वोट था। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लड़ रहा है। चुनाव आयोग के लिए अब छिपना बहुत मुश्किल होगा।

देशभर के किसानों को 3200 करोड़ फसल बीमा-क्लेम का भुगतान

- झुंझुनू में सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने बटन दबाकर ट्रांसफर की राशि

झुंझुनू (एजेंसी)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू पहुंचे। यहां हवाई पट्टी पर आयोजित समारोह में बटन दबाकर देशभर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रूपए की बीमा क्लेम राशि जारी की।इससे पूर्व कार्यक्रम में सीएम और केंद्रीय कृषि को बाजरे की बालियों से बने खास बुके देकर स्वागत किया गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से कहा-राज्य में नकली खाद और बीज बनाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है।

नया आयकर बिल पास

- दो खेल विधेयक भी पेश, खड़गे ने कहा- यह लोकतंत्र के साथ धोखा, सरकार जवाब दे

नई दिल्ली (एजेंसी) वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोपों पर हंगामे के बीच सरकार ने सोमवार को नया आयकर बिल (नंबर-2) 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल-2025 लोकसभा में पास कराया। राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल पेश हुआ, 2 स्पोर्ट्स बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए।

हालांकि इन बिलों को पेश करते समय विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे हैं। यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए।

सुप्रभात

सुनो नयन के नीर !!!
चाहे जितना भी उकसाए,
तुम्हें हृदय की पीर
पलक रेख को लाँघ न देना,
सुनो नयन के नीर !!!
तुम सोना हो तुम चाँदी हो
तुम हो माणिक मोती
जब तक नैनों में हो तुम हो
बूँद प्रलय की छोटी
ढुलक गए जो नैनों से तो,
खो दोगे तकदीर
पलक रेख को लाँघ न देना,
सुनो नयन के नीर !!!
तुम यश हो सम्मान तुम्हीं हो
तुम ही कीर्ति पताका
तुम्हीं रीढ़ हो देह नीड की
तुम सत्कार शलाका
तुम साहस हो तुम्हीं हौसला,
तुम धीरों के धीर
पलक रेख को लाँघ न देना,
सुनो नयन के नीर !!!
चाहे कष्ट हिमालय हो ले
चाहे गहरा सागर
वचन आज दो छलकेगी ना
अमरित वाली गागर
तुमको निष्फल कर देने हैं,
जग के तीखे तीर
पलक रेख को लाँघ न देना,
सुनो नयन के नीर !!!
तुमको नैनों में रहना है
हरदम डाले डेरा
तुमको करना है अंगारा
सखा साँस का फेरा
तार तार कर देनी तुमको,
बलशाली जंजीर
पलक रेख को लाँघ न देना,
सुनो नयन के नीर !!!
एक तुम्हारे दर्शन को है
आतुर यह जग सारा
यह कहने को व्याकुल है जग
हारा देखो हारा
तुमको यह रण जय करना है,
हे वीरों के वीर
पलक रेख को लाँघ न देना,
सुनो नयन के नीर !!!

- आलोकेश्वर चबडाल

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c | न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 12 अगस्त 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

ताइवान को लेकर भारत पर क्यों भड़का चीन का ग्लोबल टाइम्स

बोला- इससे नहीं होने वाला कोई फायदा

बीजिंग (एजेंसी)। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान के साथ संबंधों को लेकर भारत को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा है कि ताइवान के मुद्दे को तुल देने से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चीन के साथ संबंधों को सुधारने पर भी जोर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर यह जहर ताइवान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की हो रही वकालत के जवाब में दिया है। कई विशेषज्ञों ने बिना चीन को भड़काए भारत-ताइवान संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। हालांकि, ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत के रणनीतिक हलकों में यह आम राय है और इससे कोई लाभ नहीं होगा।

- **ताइवान से मजबूत संबंधों की वकालत कर रहे विशेषज्ञ-** ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि यह विचार नया नहीं है। इस तरह के सुझाव पहले भी दिए जा चुके हैं। 19 मई को चीन में भारत के पूर्व राजदूत विजय गोखले ने ताइवान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए शीर्षक से एक लेख लिखा था। उन्होंने लिखा, ताइवान जलडमरूमध्य में जो कुछ भी होता है, वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अभिन्न अंग होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट बोला- दिल्ली-एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करें, इन्हें शेल्टर होम में रखें, नहीं तो कार्रवाई

नईदिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। कोर्ट ने कहा,इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि दिल्ली, एमसीडी और एनएमडीसी जल्द से जल्द सभी इलाकों, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों से कुत्ते उठाएं। जरूरत हो तो इसके लिए अलग बल बनाएं।दरअसल, कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद नोटिस लेते हुए यह मामला उठाया था, जब संसद में पेश एक रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर में रेबीज के बढ़ते मामलों और बच्चों व बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई गई थी।

यूपी के फतेहपुर में मकबरे पर भगवा लहराया, बवाल-पथराव, तोड़फोड़

सड़क पर जाम लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ी

फतेहपुर (एजेंसी)। यूपी में संभल के बाद अब फतेहपुर में मंदिर-मस्जिद का विवाद शुरू हो गया। यहां सोमवार सुबह करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2 हजार लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए।

पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन लाठी-डंडे से लैस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया।

हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा करने लगे। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा-पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। करीब डेढ़ हजार मुस्लिम ईदगाह पहुंच गए।

दिल्ली में पहली बार लगाई गई मां यमुना की प्रतिमा...

नईदिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में पहली बार मां यमुना की प्रतिमा स्थापित की गई है। रिंग रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के किनारे डीडीए की

ओर से मां यमुना की ये प्रतिमा लगाई गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को यमुना प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मां यमुना की प्रतिमा स्थापित की गई है।

अपर मुख्य सचिव श्री राजन ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक ली

भोपाल (नप्र)। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन ने कहा कि विद्यार्थियों को ऑनलाईन परीक्षा की सुविधायें दी जायें। दो परीक्षाओं के बीच में पर्याप्त अंतर रखा जाये। स्वाध्यायी एवं नियमित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के प्रयास किये जायें। विद्यार्थियों को उपयोगी पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाए। जिन विद्यार्थियों की 'अपार' आई.डी. नहीं बनी है, बनवाने के प्रयास किये जाएं। सभी विश्वविद्यालय एक माह में उपाधि अपलोड कर दें। शासन स्तर पर जानकारी पूरे परीक्षण उपरांत भेजी जाएं। उच्च शिक्षा से संबंधित बैठक प्रत्येक माह संचालनालय स्तर पर आयोजित की जाये। उच्च शिक्षा के सही क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार उत्तरदायी होंगे। श्री राजन ने सोमवार को मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा ली।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर में पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

म.प्र. जबलपुर में बाइक को टक्कर मारकर पलटी स्कॉर्पियो, 5 की मौत

अनूपपुर (एजेंसी)। अनूपपुर में एक स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद पलटी खाते हुए निर्माणाधीन मकान में घुस गई। गाड़ी इतनी रफ्तार से

पलटते हुए गई की आगे का कांच टूट गया, जिससे निकलकर दो युवक बाहर गिर गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

म.प्र. में बैंक से 14 करोड़ का सोना, 5 लाख कैश लूटा

जबलपुर (एजेंसी)। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर खितौला इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने सोमवार सुबह 11 बजे बैंक लूट लिया। लुटेरों ने बैंक कर्मचारियों को कट्टा दिखाकर धमकाया। फिर 15 मिनट में 14 किलो 800 ग्राम सोना और 5 लाख 70 हजार रुपए नकद लेकर भाग निकले। लूटे गए सोने की अनुमानित कीमत साढ़े 14 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। पुलिस ने जिले में नाकाबंदी कर दी है। पूरे जबलपुर सहित कटनी, मंडला, डिंडोरी पुलिस को अलर्ट किया गया है।

पुणे में भीषण हादसा, दर्शन के लिए जा रही गाड़ी खाई में पलटी

7 महिलाओं की मौत

पुणे (एजेंसी)। महाराष्ट्र में पुणे जिले के खेड़ तालुका में एक भयानक हादसा हुआ है। कुंडेश्वर में दर्शन के लिए जा रही महिलाओं से भरी एक पिकअप गाड़ी करीब 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 25 से 30 लोग घायल हो गए। यह हादसा खेड़ तालुका के पश्चिमी इलाके में कुंडेश्वर शिव मंदिर के रास्ते में घाट इलाके में हुआ। मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है।

औषधि वाटिका विकास के लिए एम.पी. ट्रांसको में पौधारोपण

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश शासन के बिजली कंपनियों में चल रहे पौधारोपण अभियान के अंतर्गत, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के नयागांव परिसर में औषधीय पौधारोपण किया गया।

पहले चरण में मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री मुकुल मेहरोत्रा सहित विभिन्न अधिकारियों ने त्रिफला चूर्ण निर्माण में प्रयुक्त आंवला, बहेड़ा और हरड़ जैसे औषधीय पौधे रोपे। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण की शपथ ली।

मुख्य अभियंता श्री राजेश द्विवेदी ने बताया कि आगामी चरणों में अन्य औषधीय प्रजातियों का भी रोपण किया जाएगा। ऊर्जा विभाग द्वारा दिए गए पौधारोपण लक्ष्य की पूर्ति के लिए, जबलपुर मुख्यालय सहित प्रदेश भर में एम.पी. ट्रांसको के सभी कार्यालयों,

सबस्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस मुख्यालयों में चरणबद्ध तरीके से यह अभियान संचालित होगा। पौधारोपण कार्यक्रम में प्रबंध संचालक सुनील तिवारी, मुख्य अभियंता संदीप गायकवाड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

'युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी'

पुतिन-ट्रंप की बैठक से पहले जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बात

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार पीएम मोदी से साझा किए।

रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तथा शांति की शीघ्र बहाली के प्रयासों के प्रति जेलेंस्की ने भारत का आभार जताया। संघर्ष को खत्म करने के संबंध में भारत ने हर संभव सहयोग देने की बात कही है।

उ.प्र. में फर्जी अंतरराष्ट्रीय पुलिस

नकली वर्दियां-विदेश में फंसे लोगों को लाने का झांसा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिछले महीने पुलिस ने एक अवैध दूतावास के मामले में नटवरलाल की गिरफ्तारी की थी। अब इसी कड़ी में एक और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।

क्या है फर्जी पुलिस कार्यालय का केस?- फर्जी पुलिस कार्यालय से जुड़ा यह पूरा खेल उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। यहां पुलिस ने रविवार (10 अगस्त) को सेक्टर-70 में छापेमारी के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जो एक किराए के मकान से फर्जी पुलिस

दफ्तर चला रहे थे। इस घर में पुलिस दफ्तरों की तरह बोर्ड भी लगा था और इस पर 'इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो' लिखा था।

बिहार के 7 जिलों में बाढ़, 10 लाख लोग प्रभावित

- **हिमाचल में 360 से ज्यादा सड़कें बंद, उत्तराखंड में 1000 लोगों का रेस्क्यू**

नई दिल्ली/पटना/भोपाल/लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश-बिहार में तेज बारिश के कारण बाढ़ के हालात हैं। बिहार के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 10 लाख लोग प्रभावित हैं। गंगा समेत बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना जिले की 24 पंचायतें भी बाढ़ से घिरी हैं।

उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां-नाले उफान पर हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है। रविवार को एक बाइक सवार इसमें बह गया और फिर 22 घंटे तक एक पेड़ पर बैठा रहा। बाद में उसका रेस्क्यू हुआ। पिछले 24 घंटे में यूपी के 54 जिलों में 5.9 मिमी बारिश हुई। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बारिश बंद थी। पिछले दो दिन से मौसम में बदलाव हुआ है। बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त से लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) एक्टिव होगा। इससे पूरे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। अभी कुछ ही जिलों में बारिश हो रही है।हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के हुई लैंडस्लाइड के बाद एनएच-305 का औट-सैंज मार्ग बंद हैं। राज्य की 360 से ज्यादा सड़कों पर यातायात बाधित है। मानसून से जुड़ी घटनाओं में इस सीजन अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। 37 लोग अभी भी लापता हैं।

दिल्ली में सांसदों के लिए बने 184 फ्लैट्स

पीएम मोदी ने उद्घाटन कर 'सिंदूर' का पौधा भी लगाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। ये सभी फ्लैट्स टाइप-7 के मल्टी-स्टोरी अपार्टमेंट हैं। पीएम मोदी ने 'सिंदूर' का पौधा भी लगाया। इसके अलावा श्रमजीवियों से मुलाकात की। उद्घाटन के दौरान पीएम ने कहा- इन चार टावरों को बहुत सुंदर नाम दिए गए हैं, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, जो भारत की चार महान नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लाखों लोगों को जीवन देती हैं।

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' विवाद पर टिप्पणी के बाद कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना ने इस्तीफा दिया

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक सरकार में मंत्री के एन राजन्ना ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ बयान दिया था। सिद्धारमैया सरकार में सहकारिता मंत्री राजन्ना के बयान का डीके शिवकुमार कैंप ने तीखा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी आलाकमान उनके बयान को देखे। राजन्ना ने कहा था कि लोकसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हमारी पार्टी की सरकार में हुई। उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि तब हम कहां थे, हम अब आवाज क्यों उठा रहे हैं। राजन्ना के इस बयान को लेकर कांग्रेस में दरार सामने आई थी। सिद्धारमैया

समर्थक माने जाने वाले के एन राजन्ना कर्नाटक में सहकारिता मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राजन्ना अपने साफगोई के जाने जाते हैं। उन्होंने वोट चोरी के आरोपों के मुद्दे पर अपनी खुलकर राय रखी थी जो पार्टी के स्टैंड से बिल्कुल अलग थी।

- **सियासी बवंडर के बाद छोड़ा पद-** के एन राजन्ना (74) सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल में भी मंत्री बने थे। सोमवार को उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर ऐसी टिप्पणी की थी। जिसने कांग्रेस अंदर ही वोट चोरी पर दरार खड़ी कर दी थी। राजन्ना की टिप्पणी पर डीके शिवकुमार समर्थक भड़क गए थे। विवाद के तूल पकड़ने के कुछ घंटे बाद राजन्ना ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कुल सालों को छोड़ दें तो राजन्ना अपने राजनीतिक जीवन में ज्यादातर समय कांग्रेस में रही रहे हैं। वह कर्नाटक में सहकारिता क्षेत्र में बड़ी हस्ती माने जाते हैं।

भारत बोला- परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत

- **हमें सुरक्षा करना आता है; आसिम मुनीर ने कहा था- सिंधु पर बांध बना तो मिसाइल मारेंगे**

टेक्सास (एजेंसी)। भारत ने सोमवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी का जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा- परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। हमें अपनी सुरक्षा करना आता है।

किसी मित्र देश की धरती से की गई ये टिप्पणी खेदजनक है। दुनिया देख सकती है कि ऐसे बयान कितने गैरजिम्मेदाराना हैं। ये बातें उस देश पर भी शक पैदा करती हैं, जहां परमाणु हथियारों का सुरक्षित होना तय नहीं है और सेना का आतंकियों से संबंध माना जाता है।

महाकाल की निकली पांचवीं सवारी

- श्री राजाराम लोक ओरछा, मां बगलामुखी माता मंदिर, मां शारदा शक्तिपीठ की झांकियां भी हुईं शामिल

उज्जैन (नप्र)। श्रावण माह समाप्त होने के बाद श्री महाकालेश्वर भगवान की भादौ माह की सवारी सोमवार को निकाली गई। महाकाल मंदिर में भगवान चंद्रमौलेश्वर का पूजन के बाद महाकाल मंदिर से पांचवीं सवारी प्रारंभ हुईथी। हालांकि श्रावण माह में निकाली गईं सवारियों की तुलना में आज भक्तों की भीड़ कम है। सवारी में भगवान महाकाल पांच स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। श्री महाकालेश्वर भगवान की पंचम सवारी में चार जनजातीय एवं लोक नृत्य कलाकारों के दल प्रस्तुति दी। पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर, गजराज पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर श्री शिवतांडव, नंदी रथ पर श्री उमा-महेश और डोल रथ पर श्री होल्कर स्टेट के मुखारविंद शामिल हुए।

श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी निकलने के साथ ही सशस्त्र बल की टुकड़ी ने भगवान को सलामी दी। उसके बाद भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। अंतिम और राजसी सवारी 18 अगस्त को निकलेगी।

जनजातीय नृत्य की प्रस्तुति

इस बार सवारी में पालकी भजन मंडली के अलावा चार जनजातीय कलाकारों के दल भी प्रस्तुति दे रहे थे। बैतूल से गौंड जनजातीय ठाट्या नृत्य, खजुराहो से कछियाई लोक नृत्य, दमोह से बधाई लोक नृत्य और डिंडोरी के गेड़ी जनजातीय नृत्य की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र थी। सवारी के साथ मध्यप्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों की झांकियां भी शामिल हो रही हैं। इनमें श्री राजाराम लोक ओरछा, मां बगलामुखी माता मंदिर, मां शारदा शक्तिपीठ मैहर और देवीलोक मां श्री बिजासन माता धाम सलकनपुर की प्रतिकृतियां शामिल थी।

डॉ. मुसलगांवकर को मिलेगा महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान

- शिक्षा जगत में योगदान के लिए मिलेगा अवॉर्ड; भोपाल में 15 अगस्त को होंगे सम्मानित

उज्जैन (नप्र)। शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियों एवं योगदान के लिए मिलने वाला प्रतिष्ठित 'महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान' उज्जैन के दीप्ति विहार में रहने वाले, पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित 98 साल के डॉ. केशवराव सदाशिवशास्त्री मुसलगांवकर को 15 अगस्त को भोपाल में दिया जाएगा। यह अवॉर्ड उनके बेटे राजेश्वर शास्त्री ग्रहण करेंगे। मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में

श्रेष्ठतम उपलब्धियों एवं योगदान के लिए राज्य शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान के लिए 'महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान' 2023-24 के लिए उज्जैन के डॉ. केशवराव सदाशिवशास्त्री मुसलगांवकर को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया है। महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान अंतर्गत 2 लाख रुपए की सम्मान निधि, प्रशस्ति एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जाएगी। अलंकरण समारोह 15 अगस्त 2025 को रवीन्द्र भवन, भोपाल में आयोजित होगा। राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर ने बताया कि पिता डॉ. केशवराव सदाशिवशास्त्री मुसलगांवकर पहले भी 2008 में प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड, 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व भारती अवॉर्ड और 2018 में पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्हें महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है। हालांकि उम्र अधिक होने की वजह से वे अवॉर्ड लेने नहीं जा पाएंगे।

पीएम जनमन योजना के कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें : राज्यपाल मंगुभाई पटेल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि आजादी के बाद पीएम जनमन योजना जनजातीय परिवारों का जीवन बदलने वाली देश की सबसे बड़ी योजना है। जनजातीय परिवारों की खुशहाली के सभी कार्यों का जमीनी स्तर पर निरंतर निरीक्षण होना चाहिए। योजना के कार्यों की गुणवत्ता पर ग्राम पंचायत से लेकर जिलास्तर तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संबंधित अधिकारी जनजातीय परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए समय-समय पर उनसे मिलकर कार्यों का फीडबैक लें ताकि समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

राज्यपाल श्री पटेल ने सोमवार को राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ और पीएमजनमन योजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री श्री कुंवर विजय शाह उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने जनजातीय परिवारों को दी जा रही आवास सुविधाओं के संबंध में कहा कि आवासों के डिजाइन और निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आवास सुविधापूर्ण बनें। आजादी के बाद जनजातीय बंधुओं के कल्याण का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तहसील स्तर पर मैदानी अमले को लगातार निगरानी करने की आवश्यकता है। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रत्येक तिमाही में पीएम जनमन योजना में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करें। राज्यपाल श्री पटेल ने संबंधित विभागों से आग्रह किया कि अगले तीन महीनों में दिये गये लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करें। उन्होने हर घर नल से जल, सबको स्वास्थ्य, विद्युत सुविधा, सबको शिक्षा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुउददेशीय केन्द्रों की स्थिति, मोबाइल मेडिकल यूनिट, मोबाइल नेटवर्क देने आदि की समीक्षा की।

राज्यपाल श्री पटेल ने मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन की सराहना करते हुए कहा कि इनके संचालन को बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। बैठक में इन इकाइयों में स्थानीय जनजातीय बोलियों को जानने वाले अमले की तैनाती पर विचार विमर्श भी हुआ।

जनजातीय कार्य मंत्री श्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने में कई बसाहटों में किए गए नवाचारों को अपनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में तीन लाख प्रतिबद्ध लीडर्स के माध्यम से आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है। इसका उददेश्य जमीनी स्तर पर जनजातीय कल्याण है। शासन के सभी स्तरों पर तीन लाख पथ प्रदर्शकों का एक कैडर विकसित किया जा रहा है। इसमें सभी आधारभूत सेवाओं को पूरी तरह लागू किया जायेगा। इसके लिए आदि साथियों के समूह बनाये जायेंगे। राज्य, जिला, विकासखंड स्तर पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। हाल में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। उन्हें समुदाय आधारित प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव, अंतर विभागीय सहयोग, सहभागी शिक्षा के माध्यम से जनजातीय सशक्तीकरण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ राजभवन के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री संदीप यादव, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री मनीष सिंह, सचिव स्कूल शिक्षा श्री संजय गोयल, सचिव महिला बाल विकास श्रीमती जीवी रश्मि, अपर सचिव पंयायत एवं ग्रामीण विकास श्री दिनेश जैन, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीमती सलोनी सिडाना एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने वृंदावन में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण से की सौजन्य भेंट

महाराज जी के मुखारविंद से निकला प्रत्येक वचन धर्म का प्रतिमान

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रविवार को सपरिवार वृंदावन की पावन भूमि पर स्थित श्री हित राधा केली कुंज पहुंचकर श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण से सौजन्य भेंट की। उन्होंने कहा कि संतों का सानिध्य प्राप्त होना जनसेवा से अर्जित पुण्य कर्मों का संचित फल है। उन्होंने कहा कि महाराज जी के मुखारविंद से निकला प्रत्येक वचन धर्म का प्रतिमान है और उनके सान्निध्य में बिताया गया प्रत्येक क्षण मन, वचन और कर्म को पवित्र करने वाला है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने इस भेंट को अपने जीवन की अमूल्य आध्यात्मिक निधि बताते हुए कहा कि पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद सदैव उन्हें लोककल्याण के कार्यों के लिए प्रेरित करता रहेगा।

सिद्धनाथ के शिवडोले में 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे

खरगोन (नप्र)। खरगोन जिले में श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा पर्व शिव डोला सोमवार को धूमधाम से शुरू हुआ। भगवान सिद्धनाथ महादेव और महाबलेश्वर महादेव की शाही सवारी आज नगर भ्रमण पर निकली है। इस बार शिवडोले को उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर भव्य स्वरूप दिया गया है।

सुबह मंदिर में विशेष पूजा और महाआरती के बाद भगवान को फूलों से सजी पालकी में विराजित किया गया। इसके बाद भावसार धर्मशाला से भगवान सिद्धनाथ का विशेष रथ यात्रा के रूप में नगर भ्रमण शुरू हुआ।

शिवडोले की महाआरती में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार और कलेक्टर भव्या मित्तल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और श्रद्धालु शामिल हुए। जिला

प्रशासन के अनुसार, इस धार्मिक आयोजन में दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इधर, शाम 4:30 तक करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौके पर पहुंच चुके हैं।कलेक्टर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचीं।

शाम को गर्मी कम होते हो श्रद्धालुओं के शिवड़ोले में पहुंचना लगातार जारी है। भीड़ का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने झांकियां के साथ व्यस्थाओं का मुआयना किया। उन्होंने झांकियां समय से डोला मार्ग बढ़ाने के प्रति झांकी अखाड़ा समितियां को कहा।

शिव डोला में धूप कम होते ही श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक अनुमानित संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। श्रद्धालुओं का तेजी से पहुंचना जारी है।

नरेला विधानसभा क्षेत्र में रक्षाबंधन महोत्सव शुरू

भोपाल (नप्र)। नरेला विधानसभा क्षेत्र में सोमवार से विश्व का सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव शुरू हो गया। सुभाष नगर खेल मैदान से प्रारंभ हुए इस 17वें महोत्सव को इस वर्ष लव जिहाद और नशे के खिलाफ जन-जागरण अभियान को समर्पित किया गया है। आयोजन का शुभारंभ होते ही हजारों बहनों ने प्रदेश के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग को राखी बांधी और दोनों सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया।

मंत्री विश्वास सारंग को इस अवसर पर बहनों ने 'ऑपरेशन सिंदूर राखी' बांधी। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त तक विश्वास

विजय वाहिनी की महिला कार्यकर्ता घर-घर जाकर, स्कूल, कॉलेज, जिम, कोचिंग सेंटर और हॉस्टल में लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगी। साथ ही नशे के दुष्प्रभावों पर भी जन-जागरण किया जाएगा।

लव जिहाद पीड़ित परिवारों को मिलेगी कानूनी मदद

मंत्री सारंग ने बताया कि जिन परिवारों की बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं, उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह और मदद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा, हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार नहीं होने देंगे। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हर बहन-बेटी को सुरक्षित वातावरण मिले।

पैर दबवाने वाली टीचर और स्कूल प्रिंसिपल को नोटिस

भोपाल (नप्र)। राजधानी के गांधीनगर स्थित शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एक महिला शिक्षक का छात्र से पैर दबवाने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ लिया गया है। सोशल मीडिया पर रविवार को पूरे दिन चर्चा में रहे इस वीडियो पर सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित टीचर और स्कूल प्रिंसिपल दोनों को नोटिस जारी कर दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। जिसे तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।यह वीडियो गांधीनगर स्थित शासकीय महात्मा गांधी उ.मा.वि. का है। लंच ब्रेक के बाद जब अधिकांश कक्षाओं में बच्चे शांत होकर पढ़ाई कर रहे थे, तभी कक्षा 4 से शोरगुल की आवाज आ रही थी। यह स्कूल की एकमात्र कक्षा है, जहां बच्चे जमीन पर बैठते हैं। यहां महिला शिक्षक अनीता श्रीवास्तव कुर्सी पर बैठी थीं, उनका एक पैर सामने रखी दूसरी कुर्सी पर था, जिसे उसी कक्षा का एक छात्र दबा रहा था। स्कूल के अन्य शिक्षकों के अनुसार, ऐसी घटना यहां पहले भी हो चुकी है, इसलिए उन्हें यह नया नहीं लगा।

सफाई देते हुए टीचर बोलीं- गेट पर गड्ढे में पैर मुड़ गया था

महिला शिक्षक अनीता श्रीवास्तव ने सफाई देते हुए कहा था कि क्लास में प्रवेश करते समय गेट पर टूटी टाइल से बने गड्ढे में मेरा पैर मुड़ गया। बच्चों ने मुझे संभालकर कुर्सी पर बैठाया और एक बच्चा प्रेमभाव से पैर दबाने लगा ताकि दर्द कम हो सके।

प्रिंसिपल का जवाब

स्कूल प्रिंसिपल ए.पी. सिंह ने कहा कि घटना के समय वे एक अन्य सरकारी कार्य की जांच में बाहर थे और इसके सबूत के तौर पर उन्होंने वीडियो व जीपीएस अटैच फोटो भी दिए हैं। उनकी अनुपस्थिति में चार्ज हेड मास्टर आर.के. खीर के पास था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ नोटिस क्यों जारी हुआ। जांच कमेटी गठित कर दी गई है और रिपोर्ट 3 दिन में जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी जाएगी। संबंधित टीचर से भी जवाब मांगा गया है।

कार्रवाई होना तय

जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने स्पष्ट किया है कि तीन दिन में मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामला केवल अनुशासन का नहीं बल्कि शिक्षक-छात्र संबंध की गरिमा और सरकारी स्कूलों की छवि से भी जुड़ा है।

जबलपुर, रीवा और सागर संभाग में बारिश का अलर्ट

भोपाल, इंदौर-उज्जैन में धूप खिलेगी; उज्जैन में बारिश के लिए पटेल को गधे पर बिठाया

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के 10 जिलों में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट है। ट्रफ लाइन की एक्टिविटी होने से यहां तेज बारिश हो सकती है। वहीं, भोपाल, इंदौर और उज्जैन में मौसम साफ रहेगा। यहां तेज धूप खिली रहेगी।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश होगी। 12 अगस्त को भी पूर्वी हिस्से में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है।

इधर, उज्जैन क्षेत्र में 15 दिन से बारिश नहीं होने के कारण ग्रामीण टोटके कर अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं। उन्हेल गांव में पटेल, लखन पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान में पांच बार घुमाया गया। ग्रामीणों की मान्यता है कि इस अनोखी परंपरा से जल्द ही बारिश होती है।

खजुराहो में 24 घंटे में गिरा 3.4 इंच पानी, सागर में ढाई इंच बारिश हुई

मध्यप्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई। छतरपुर के खजुराहो में सबसे ज्यादा 3.4 इंच पानी गिर गया। सागर में 2.4 इंच, खंडवा में 2 इंच, नरसिंहपुर-दमोह में डेढ़ इंच बारिश

दर्ज की गई। भोपाल, उमरिया, उज्जैन, नर्मदापुरम, श्योपुर, सीधी, सीहोर, बड़वानी, शाजापुर, देवास समेत कई जिलों में पानी गिरा।

दो दिन बाद बनेगा नया सिस्टम

बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त से लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) एक्टिव होगा। इससे पूरे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। अभी कुछ ही जिलों में बारिश हो रही है।

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया-अगले 3 दिन तक कई जिलों में भारी बारिश होगी। 13-14 अगस्त से बारिश की एक्टिविटी तेज होगी। यानी, अगस्त के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में भारी बारिश का दौर बना रहेगा।

दूसरे सप्ताह में ही तेज बारिश के आसार

वैज्ञानिकों के अनुसार, अगस्त के दूसरे सप्ताह में तेज बारिश का दौर शुरू होगा, जो आखिरी तक चलता रहेगा। ऐसे में बारिश का कोटा अगस्त में ही पूरा हो जाएगा। हालांकि, अब तक ग्वालियर समेत 10 जिलों में कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों की तस्वीर बेहतर नहीं है।

पूर्वी हिस्से यानी, जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में औसत से 37 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से यानी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में 25 प्रतिशत बारिश अधिक हुई है।

इंदौर संभाग में सूखे जैसी स्थिति, सबसे कम पानी गिरा, उज्जैन भी पिछड़ा,भोपाल में आधी बारिश

मानसूनी सीजन को करीब ढाई महीना बीतने को है। मध्यप्रदेश में अब तक औसत 29.3 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे की 79 प्रतिशत है। ग्वालियर समेत 10 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है, जबकि इंदौर संभाग के 8 में से 6 जिलों में सूखे जैसी स्थिति है। उज्जैन संभाग भी पिछड़ा है। दूसरी ओर, ग्वालियर, जबलपुर संभाग की तस्वीर सबसे बेहतर है। भोपाल में आधी से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 10 जिले- ग्वालियर, राजगढ़, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मुरैना और श्योपुर में बारिश का कोटा पूरा हो गया है। इनमें से कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां आंकड़ा डेढ़ सौ प्रतिशत तक पहुंच गया है। हालांकि, अगस्त का पहला पखवाड़ा सूखा ही बीत रहा है। कुछ जिलों को छोड़ दें तो प्रदेश के बाकी हिस्से में तेज बारिश नहीं हुई है। दूसरे पखवाड़े में ही तेज बारिश होने के आसार है। बता दें कि प्रदेश में 16 जून को मानसून ने आमद दी थी।

संपादकीय

समझौते पर ईरान का ग्रहण

मध्य एशिया के दो देशों आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 37 साल से चल रहे नगोर्नो काराबाख संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस जल्दबाजी में दोनो देशों के बीच शांति समझौता कराया है, वह अब ईरान की धमकी के बाद खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। ट्रंप की पहल पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव और आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने 1 अगस्त को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन समझौते के एक हफ्ते के भीतर ही ईरान ने इसे खारिज कर कहा है कि वो विवादित क्षेत्र में प्रस्तावित ट्रंप कॉरिडोर किसी भी सूरत में नहीं बनने देगा। ईरान के इस रूख से इस कथित शांति समझौते के लिए ट्रंप की नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत भी खटाई में पड़ गई है। गौरतलब है कि आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों ही 35 पहले तक पूर्व सोवियत रूस का हिस्सा थे और सोवियत रूस के विखंडन के बाद स्वतंत्र देश बन गए थे। लेकिन दोनों के बीच नगोर्नो काराबाख पर अधिपत्य 37 सालों से विवाद का मुद्दा रहा है। सोवियत रूस के जमाने में यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल अजरबैजान राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र था। इसकी आबादी करीब एक लाख है। लेकिन आर्मीनिया का दावा है कि नगोर्नो काराबाख ऐतिहासिक रूप से उसके देश का हिस्सा है। इसी कारण दोनों देशों में कई बार सशस्त्र संघर्ष हो चुका है। आर्मीनिया ईसाई बहुल है और अजरबैजान शिया मुस्लिम बहुल देश है। दोनों देश ईरान की उत्तरी सीमा से लगते हैं। इसलिए ईरान की दिलचस्पी सीधे तौर पर नगोर्नो काराबाख में है। अंतराष्ट्रीय राजनीति में आर्मीनिया को रशिया का समर्थन है तो अजरबैजान को ईरान का। जबकि खुद नगोर्नो काराबाख के लोग स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहते हैं। इस माह के शुरू में दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते में सीमा निर्धारण, सुरक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाने के प्रावधान शामिल हैं। लेकिन समझौते में सबसे विवादास्पद प्रावधान जंगेजुर गलियारे का है, जिसे 'ट्रंप रूट फॉर प्रास्पेरिटी' नाम देकर अमेरिका को वहां विकास के लिए विशेष अधिकार देना है। साथ ही आर्मीनिया के दक्षिण में स्थित नखचिवन स्वायत्त गणराज्य को आर्मीनिया के माध्यम से बिना किसी जांच चौकी के अजरबैजान से जोड़ना है। यह गलियारा बनने पर यूरोप से अज़रबैजान और व्यापक मध्य एशिया तक लोगों और सामानों का आवागमन रूस या ईरान से गुज़रे बिना संभव हो सकेगा। यही ईरान को मंज़ूर नहीं है। क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप कॉरिडोर के जरिए इस क्षेत्र में अमेरिका की सीधी मौजूदगी, जो ईरान के लिए खतरा है। दूसरे खुद नगोर्नो काराबाख की ज्यादातर आबादी ईसाई है। इसलिए आर्मीनिया उसे अपना हिस्सा मानता है। अजर बैजान को यह स्वीकार नहीं है। दोनो देशों के बीच करार हुए अभी दो हफ्ते भी नहीं हुए हैं कि ईरान ने साफ कह दिया है कि वह ट्रंप कॉरिडोर नहीं बनने देगा। यानी ऐसी कोशिशें हुई तो वह हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही चल रही तनातनी सीधे युद्ध में तब्दील हो सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए घातक होगी। जहां तक भारत का सम्बंध है तो हमारे यू तो तीनों देशों से रिश्ते ठीक हैं, लेकिन हाल के भारत पाक सीमित युद्ध में जिस तरह अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया, उससे भारत अजरबैजान रिश्तों में कड़वाहट आई है। दूसरी तरफ भारत आर्मीनिया को हथियार बेचता है। इस पूरे प्रकरण का एक सबक यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए कितने लालायित हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।

लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर सवाल के अर्थ

नज़रिया

तनवीर जाफ़री

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

कई बार विश्व के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल हमारे विशाल देश की चुनावी प्रक्रिया को देखने व समझने के लिये चुनावों के दौरान भारत आते रहे हैं। उधर भारतीय चुनाव आयोग जहां इस विशाल चुनाव के सफल संचालन का हमेशा श्रेय लेता आया है वहीं इन्हीं चुनावों में प्रायः कहीं न कहीं चुनावी धांधली के आरोप भी लगते रहे हैं। विगत में लोकसभा व विधानसभा के कुछ चुनाव तो ऐसे भी संपन्न हुये जिनके परिणामों ने चुनाव पूर्व होने वाले सभी सर्वेक्षणों को पूरी तरह नकार दिया। वैसे भी जब से देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से वोट पड़ने शुरू हुये हैं उसी समय से मतदान की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, व राज्यसभा सांसद जी.वी.एल. नरसिम्हा राव जैसे कई प्रमुख नेताओं ने समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुये इसके इस्तेमाल का विरोध किया है।

भारत वर्ष को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जहां दुनिया जानती है वहीं यहाँ होने वाले चुनाव भी पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कई बार विश्व के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल हमारे विशाल देश की चुनावी प्रक्रिया को देखने व समझने के लिये चुनावों के दौरान भारत आते रहे हैं। उधर भारतीय चुनाव आयोग जहां इस विशाल चुनाव के सफल संचालन का हमेशा श्रेय लेता आया है वहीं इन्हीं चुनावों में प्रायः कहीं न कहीं चुनावी धांधली के आरोप भी लगते रहे हैं। विगत में लोकसभा व विधानसभा के कुछ चुनाव तो ऐसे भी संपन्न हुये जिनके परिणामों ने चुनाव पूर्व होने वाले सभी सर्वेक्षणों को पूरी तरह नकार दिया। वैसे भी जब से देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से वोट पड़ने शुरू हुये हैं उसी समय से मतदान की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, व राज्यसभा सांसद जी.वी.एल. नरसिम्हा राव जैसे कई प्रमुख नेताओं ने समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुये इसके इस्तेमाल का विरोध किया है।

बहरहाल 2014 के चुनावों के बाद से ईवीएम की विश्वसनीयता का सवाल विपक्षी दलों द्वारा किया जाने लगा है। पिछले एक दशक से होने वाले लगभग सभी चुनावों में ईवीएम से होने वाली धांधलियों के अनेक आरोप लगते रहे हैं। कभी ईवीएम बदलने के तो कभी ईवीएम चोरी होने के। कभी मतदाताओं को यह कहते सुना गया कि उन्होंने वोट तो कहीं और दिया परन्तु वीवीपीएट मशीन किसी दूसरे निशान पर वोट पड़ा बताती है। हालांकि पिछले चुनावों में कई बार कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें भी बनीं परन्तु ईवीएम का विरोध निरंतर जारी रहा। दिल्ली में जंतर मंतर पर अनेक बार ईवीएम विरोधी प्रदर्शन भी हुये। देश के वकीलों का एक बड़ा वर्ग खुलकर ईवीएम के विरोध में खड़ा हुआ परन्तु सरकार व चुनाव आयोग ईवीएम पर ही विश्वास जताते रहे। परन्तु अब मामला ईवीएम की विश्वसनीयता से भी आगे बढ़कर वोटर लिस्ट में हो रही भयंकर धांधली का उजागर हुआ है। और इसका भंडाफोड़ किया है लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी ने।

गत 7 अगस्त को राहुल गांधी ने 'बड़े पैमाने पर हो रही चुनावी धोखाधड़ी को उजागर किया। उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य लोकसभा क्षेत्र में, महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मतदाता सूचियों में, विशिष्ट अनियमितताओं को उजागर किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि केवल (महादेवपुरा) क्षेत्र में, कुल 6.5 लाख मतदाताओं में से, 1 लाख से अधिक फ़र्ज़ी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया, जिससे

उस क्षेत्र में भाजपा की 1,14,046 मतों के महत्वपूर्ण अंतर से जीत हुई। उन्होंने मतदाता सूची में विसंगतियों के उदाहरण दिए और मतदाता सूचियों में हेराफेरी, डुप्लिकेट मतदाता,साक्ष्यों का विनाश और पारदर्शिता का अभावः,असामान्य मतदान पैटर्न आदि विषयों को प्रमाण सहित उठाया। गांधी ने कथित वोट चोरी में शामिल चुनाव आयोग के शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने उनके कार्यों को 'देशद्रोही' और राष्ट्रहित के विरुद्ध क़रार दिया, और कहा कि कांग्रेस उन्हें जवाबदेह ठहराएगी। राहुल गांधी ने छः महीने की कड़ी मशक़्क़त के बाद कांग्रेस द्वारा जुटाए गए इन सबूतों को 'परमाणु बम' का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इनके सार्वजनिक प्रकाशन से चुनाव आयोग की भूमिका उजागर हो जाएगी और उसके पास 'छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी।'

दरअसल राहुल गाँधी के मांगने पर चुनाव आयोग ने लगभग तीन क्विंटल से भी अधिक काग़ज़ों के विशाल बण्डल उन्हें भेजे थे। राहुल ने अपने विशेषज्ञों के साथ इन काग़ज़ात में से केवल 4 किलो काग़ज़ का चुनाव किया और बड़ी बारीकी से उनका डेटा अध्ययन किया। जब इन काग़ज़ात में ही वोटों की बड़ी चोरी पकड़ी गयी तभी राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुँच गये कि जब 4 किलो काग़ज़ात फ़र्ज़ी हैं तो शेष सैकड़ों किलो काग़ज़ात भी फ़र्ज़ी ही हैं। गोया अब सवाल महादेवपुरा विधानसभा का ही नहीं बल्कि देश की प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा सीटों के चुनाव का है ? यही वजह है कि अब राहुल गाँधी देश की सभी 543 लोकसभा का वोटर डेटा मांग रहे हैं। वह इसीलिये 'मशीन रिडेबल' डेटा की मांग कर रहे हैं ताकि डेटा और फ़ोटो एनालिसिस हो सके। कांग्रेस का मानना है कि यदि चुनाव आयोग ने मशीन डेटा दे दिया तो मात्र 7 दिनों में हर एक वोटर की पहचान हो जाएगी और SIR करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और मशीन डेटा से रोहंगिया, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली जो भी फ़र्ज़ी मतदाता होंगे सभी सामने आ जायेंगे।

परन्तु आश्चर्य है कि भारतीय इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा व चुनाव आयोग दोनों ही एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। वही पुराना राग अलाप रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप 'निराधार', 'शर्मनाक' और 'लोकतंत्र का अपमान' हैं। और भाजपा नेताओं के अनुसार ये आरोप कांग्रेस की हार से उपजी हताशा का परिणाम हैं। उन्होंने कांग्रेस को क़ानूनी रास्ता अपनाने की चुनौती दी और निर्वाचन आयोग की 'निष्पक्षता' का बचाव किया। साथ ही भाजपा ने इसे कांग्रेस द्वारा संवैधानिक संस्थानों पर हमले के रूप में वर्णित किया।

याद कीजिये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का वह आरोप जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लोकसभा क्षेत्र में साढ़े तीन लाख वोटरों के नाम काट दिये गए थे। किसने कटवाये थे यह नाम क्यों काटे गये ? ऐसी अनियमिताओं की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं तो किसकी है ? किसके इशारे पर होता है यह काम ? क्या यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे के ख़िलाफ़ 'साजिश' नहीं? राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि महाराष्ट्र में केवल पाँच महीनों में लगभग 40 लाख संदिग्ध मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। उधर महाराष्ट्र में ही कई प्रत्याशी भी यह कहते सुने गये कि भाजपा नियंत्रित अधिकांश बूथ पर शाम पांच बजे के बाद 'अनजान मतदाताओं' की बड़ी भीड़ इकठ्ठा हुई थी। कौन थे कहां से आये थे ये मतदाता ? चुनाव आयोग को नेता प्रतिपक्ष के प्रत्येक संदेह व आरोप का संतोषजनक उत्तर देना चाहिये ताकि देश और दुनिया यह जान व समझ सके कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव निष्पक्ष संपन्न होते हैं।

पर्यावरण

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

जलवायु परिवर्तन पर बड़े देशों की जिम्मेदारी तय

हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा दिया गया ऐतिहासिक फैसला वैश्विक जलवायु न्याय और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। इस फैसले के ज़रिए यह संदेश दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल एक वैज्ञानिक या पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों से सीधे जुड़ा मसला बन चुका है।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर 23 जुलाई, 2025 को यह फैसला सुनाया। यह फैसला दक्षिण प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीपीय देश, वानुअतु द्वारा लाए गए एक मामले के बाद आया है, जिसे बढ़ते समुद्र स्तर से ख़तरा है और जिसका समर्थन 131 अन्य देशों ने किया है। इसमें केन्या, घाना, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, कैमरून, सेरा लिओन, मॉरीशस, बुर्किना फासो, और मिस्र ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के बारे में अपनी अपनी दलीलें पेश कीं थी। न्यायालय ने उनकी दलीलों को स्वीकार कर लिया कि विकासशील देशों ने वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान दिया है, फिर भी वे विकसित देशों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से ज़्यादा प्रभावित हैं।

यह फैसला खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें भविष्य की पीढ़ियों और जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित समुदायों के अधिकारों की बात की गई है, जो अब तक के अंतरराष्ट्रीय कानून में बहुत कमज़ोर ढंग से पेश होते थे। जलवायु परिवर्तन एक अस्तित्वगत संकट है जो मानवता के भविष्य के लिए ख़तरा बन सकता है।

इस फैसले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पहली बार यह औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जलवायु परिवर्तन से निपटना सभी देशों की कानूनी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि अत्यधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले देशों को अधिक जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर न्याय का यह सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि जलवायु परिवर्तन का संकट उन सीमाओं को नहीं मानता जो देशों की भौगोलिक पहचान तय करती हैं – इसके दुष्प्रभाव वैश्विक हैं।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह साफ़ कहा है कि जो देश वायुमंडल में सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैसें छोड़ रहे हैं, वे केवल अपने नागरिकों के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पर्यावरणीय और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण किसी सीमा पर नहीं रुकता – इसका प्रभाव अफ्रीका के किसानों से लेकर एशिया के तटीय इलाकों तक और पैसिफिक द्वीप समूह के अस्तित्व तक को खतरे में डालता है।

यही कारण है कि इस फैसले को एक वैश्विक नैतिक और कानूनी दिशा-निर्देश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि विश्व समुदाय, विशेष रूप से विकसित और उच्च उत्सर्जन वाले देश, अब अपनी जलवायु नीतियों में जवाबदेही और न्याय को प्राथमिकता देंगे।

विशेष रूप से प्रशांत महासागर में बसे छोटे द्वीपीय देश जैसे टुवालू, मार्शल आइलैंड्स, किरीबाती आदि जो समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस फैसले को अपने लिए एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। अब उनके पास इस आधार पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और अदालतों में मुकदमे दायर करने की ठोस ज़मीन है कि जलवायु संकट के लिए जिम्मेदार बड़े देश उनकी ज़िंदगियों और भूमि को खतरे में डाल रहे हैं।

वर्तमान में दुनिया के लगभग 60 देशों में 3000 से अधिक जलवायु न्याय से जुड़े मुकदमे लंबित हैं, जिनमें सरकारों और जीवाश्म ईंधन आधारित कंपनियों पर यह आरोप है कि वे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में नाकाम रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यह फैसला इन सभी मुकदमों को एक नैतिक और कानूनी बल प्रदान कर सकता है।

अदालत ने यह महत्वपूर्ण बात भी कही कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याएं मानवाधिकारों को भी प्रभावित करती हैं, विशेषकर स्वास्थ्य, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, आवास और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को। यह विचार अब अंतरराष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बन रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर साफ़ हवा और सुरक्षित पर्यावरण नहीं मिल रहा, तो उसके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

यह सोच मानव अधिकारों की आधुनिक परिभाषा को विस्तारित करती है जिसमें अब सिर्फ सरकार की ओर से दिए गए अधिकार नहीं, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की पूर्ति भी अनिवार्य हो जाती है।

यह विडंबना ही है कि एक ओर पर्यावरण संरक्षण को लेकर वैश्विक अदालतें जागरूक हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर ज़मीन पर पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग लगातार खतरे में हैं। वर्ष 2023 में दुनिया भर में कम से कम 196 पर्यावरण रक्षकों की हत्या कर दी गई। इनमें से अधिकतर मामले उन क्षेत्रों से जुड़े हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, अवैध खनन, वनों की कटाई या औद्योगिक परियोजनाओं का विरोध किया गया था।

'ग्लोबल विटनेस' द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत सहित 20 से अधिक देशों के 200 से अधिक पर्यावरण कार्यकर्ताओं से बातचीत के आधार पर यह सामने आया कि 90 प्रतिशत से अधिक को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और 25 प्रतिशत से अधिक पर हिंसक हमले हुए। इनमें से कई मामलों में कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे चलाए गए, उनके संस्थान बंद किए गए, बैंक खातों को सील किया गया और उन्हें 'राष्ट्रविरोधी' करार दे दिया गया।

अब खतरे सिर्फ मैदानों और जंगलों तक सीमित नहीं हैं। सोशल मीडिया और डेटा निगरानी के इस दौर में, पर्यावरण कार्यकर्ताओं की निजी जानकारियां साझा करके उन्हें बदनाम या निशाना बनाना एक आम रणनीति बन चुकी है। 'रेड टैगिंग' जैसी कार्रवाइयों के ज़रिए कार्यकर्ताओं को देशद्रोही बताया जाता है, और कई बार वे 'गायब' कर दिए जाते हैं – जैसा कि फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया में बार-बार सामने आया है।

भारत में भी कार्यकर्ताओं पर यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत मुकदमे चलाए गए हैं, जिससे साफ होता है कि जलवायु न्याय की लड़ाई केवल वातावरणीय नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष बन चुकी है। यह सच है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है – यानी कोई देश उसे मानने को बाध्य नहीं है। लेकिन इसका नैतिक प्रभाव और वैश्विक दबाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यह फैसला सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गया तो यह एक खोया हुआ अवसर होगा।

अब ज़रूरत है कि राष्ट्रीय सरकारें अपने जलवायु कानूनों और नीतियों में इस फैसले को शामिल करें। साथ ही पर्यावरण कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए जाएं। इसके अलावा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर कठोर निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था की जाए। और सबसे ज़रूरी आम जनता, मीडिया और नागरिक समाज इस विषय को अपनी बातचीत के केंद्र में लाएं।

जलवायु संकट अब भविष्य का विषय नहीं है यह आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यह फैसला एक कानूनी दस्तावेज़ भर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है और साथ ही एक मौका भी कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, और एक न्यायपूर्ण, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।

पर्यावरण कार्यकर्ता, जो आज ज़मीन, जंगल, नदियों और हवा के लिए लड़ रहे हैं उनके संघर्ष केवल उनके समुदाय के नहीं, बल्कि पूरे मानवता के संघर्ष हैं। उन्हें सुरक्षा देना, समर्थन देना और उनकी बात को सुनना, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। क्योंकि अंततः यदि पृथ्वी सुरक्षित नहीं, तो मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं।

सामयिक

सुरेश सौरभ

खान सर की कलाई में बंधी राखियों के मायने

'बहुत सी बहनें अपने भाईयों को राखी बांधने नहीं गयीं। आपको राखी बाँध रही हैं, आप को कैसा फील हो रहा है'-एक एंकर पटना वाले खान सर से सवाल करता है, राखी बंधवाते हुए, तब उनका प्रतिउत्तर ,'यह तो मेरा नसीब है। अच्छा लग रहा। यह हमारी संस्कृति है, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत से अच्छी संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं है।' इसके साथ ही राखी बांधने आयीं हजारों बहनों के उज्वल भविष्य की वह कामनाएं भी करते हैं। दूर-दूर से राखी बांधने आयीं बहनें (छात्राएं) भी खान सर को कोई पिता तुल्य, तो कोई भगवान तुल्य बतातीं हैं।

राखी बांधने आयीं हजारों, लड़कियों के लिए खान सर ने 156 प्रकार के व्यंजन बनवाए। इसे क्या कहेंगे आदर्शवाद, यथार्थवाद, भौतिकतावाद या आभासी दुनिया का प्रचारवाद। स्कूल कॉलेज या कोचिंग जगत हो या कॉरपोरेट जगत के प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, आज बाजारवाद हर जगह हावी है, बाजारवाद हर तीज-त्योहार पर अपने लाभ का सुनहरा अवसर खोजता है, यह अवसर कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोना नहीं चाहता,इसलिए त्योहारों पर बाजारवाद के प्रभावों और परिणामों को कोई नजर अंदाज नहीं कर सकता है, कहीं-कहीं इसके परिणाम सार्थक, रचनात्मक और दूरगामी साबित होते हैं, फिर चाहे वह खान सर का राखीबंधन वाला महोत्सव ही क्यों न हो।

दो माह पहले पत्नी बीमार हुईं जिला अस्पताल में भर्ती कराया। रात 12 बजे का वक्त था-पानी की बोतल भरने के लिये, पास के वाटर कूलर के समीप गया। बोतल भरते समय, लगभग 25 साल का एक युवक मुझे एकटक देख रहा था, मैंने अनायास पूछा-'क्या बात है।'

'सर मैंने आप को कहीं देखा है। शायद आप कभी श्रृंगारपुर गांव में पढ़ाते थे।' वह नरमी से बोला।

'अरे! हां 15 साल हुए होंगे।' मैंने आहिस्ते से जवाब दिया। तब वह उत्साहित होकर बोला, -'हां याद आया सर! आप हिन्दी पढ़ाते थे-बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आप के जैसा फिर कोई मुझे न मिला।' मैंने बोतल संभाली हंसते हुए बोला, 'ऐसा नहीं बेटा, मुझसे ज्यादा, दुनिया में तमाम अच्छे शिक्षक हैं।' उसकी आँखों में झलकती मान-सम्मान की उस दिलकश तासीर से मैं अभिभूत हुआ। अपना पढ़ाया, एक बच्चा भी अगर बरसों बाद सम्मान करे, या याद रखें, तो मैं समझता हूँ, यही अध्यापक की सबसे बड़ी पूंजी है-निश्चित रूप से यही खान सर की वास्तविक पूंजी है- कम फीस, बच्चों के प्रति आत्मीयता, अपनापन और क्षेत्रीय भाषा के साथ पढ़ाने का, उनका अनोखा खास लहजा,उनको सबसे अलग और यूनीक बनाता है, जिससे अध्यापन के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली है। आभासी दुनिया ने श्रेष्ठ शिक्षकों को अधितम छात्र-छात्राओं तक जोड़ा है, फिर चाहे वह खान सर हो, विकास दिव्यकीर्ति हो, अलख पांडे (फिजिक्स वाले) या फिर अपने रसगुल्ला ताकिया कलाम के लिये चर्चित कुमार गौरव आदि शिक्षक। श्रेष्ठ शिक्षक किसी भी देश की सम्पत्ति होते हैं। बदलते समय के परिदृश्य के साथ चलना ही, हमारी नियति है। हमारे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में श्रेष्ठ शिक्षकों की कमी नहीं है, पर आभासी दुनिया के नवाचारों के प्रति अधिकतर शिक्षकों की अरूचि के चलते, वह डिजिटल दुनिया के शैक्षिक नवाचारों में अपनी पहुंच या पकड़ नहीं बना पा रहे हैं,। ज्ञानवाणी, स्वयंप्रभा, पीएम ई विद्या, जैसे सरकारी रेडियो टीवी चैनलों से बच्चे लाभान्वित तो जरूर हो रहें हैं, पर उतना लाभ नहीं मिल रहा, जितना निजी चैनलों से मिल रहा है। निजी चैनलों के लोकप्रिय होने मुख्य कारण यहीं है कि उनके विषयों की विविधता, छात्रों से सीधा संवाद, विषयों की नवीनता, समय-समय जरूरी विषयों पर भौतिक संवाद, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या सामान्य परीक्षाओं के बारे में समयानुकूल सूचनाएं देना, निश्चित समय पर नोट्स, पैक्स्टिस सेट, और प्रतियोगिता में सफल होने के लिये जरूरी छद्म साक्षात्कारों से छात्रों को तैयारी कराना।

आज आवश्यक है कि आभासी दुनिया के नवाचारों से अधिकतम हम सब शिक्षक जुड़े, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य उज्वल हो, श्रेष्ठ शिक्षक एक मशाल की तरह होते हैं, जो पूरे समाज को प्रकाशित करते हैं। बेहतर भविष्य का निर्माण करतें हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. प्रेमचंद द्वितीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

किस्म - किस्म के टालमटोल टूल

मॉर्निंग वॉक के दौरान पंडित शिवनारायण जी पंडिताइन द्वारा हर दिन वॉकिंग में टालमटोल को लेकर काफी खपा है और टालमटोल की प्रवृत्ति को लेकर मॉर्निंग वाकियों के बीच चर्चा में बोले, दुनिया में टालमटोल के किस्म-किस्म के टूल मौजूद है। कई टालमटोल करने के ऐसे हुनरबाज है कि वे काम को टाल कर अच्छे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट की कगार पर पहुंचा देते हैं और नीतियों को टालमटोल कर टालू मिक्सर के बॉक्स में डाल देते हैं।

टालमटोल के टालू मिक्सचर जैसे नए शब्द को सुनकर घूमने में हमेशा टाला लेने वाले कमल जी बोले, प्रोफेसर तिवारी सेवानिवृत्ति के बाद जाने के पहले कस्बे वालों को टालू मिक्सचर जैसे एक नए शब्द की सौगात दे गए। ऑफिस के बड़े बाबू हर कार्य को टालने और टालमटोल करने से वे उसे टालू मिक्सचर कह कर पुकारते। टालमटोल करने की प्रवृत्ति उनके दिमाग में ऐसी घर कर गई थी कि वह किसी काम से इंकार नहीं करते और काम भी नहीं करते। काम को कैसे टाला जाए तो वह बड़े बाबू से सीखा जा सकता था।

टालम टोल के पर्याय बने बड़े बाबू ने अपनी टेबल पर फाइलों का अंबार लगा रखा था जो भी व्यक्ति उनके पास काम कराने आता भी उसे कैसे टाले इसमें उनकी महारत हासिल थी। ऑफिस की अपनी टेबल पर उसे ले जाते वह टेबल पर धूल खा रही लालफीते में बंद पड़ी फाइलों को दिखाते, धूल खा रहे कंप्यूटर को ऑन कर बताते कि इसमें काम की इतनी फाइल इकट्ठा हो गई है कि फॉर्मेट की नौबत आने का कहकर काम को टाल देते। बड़े बाबू के आजकल के बहाने ने उनके हर काम में पसीना बहा दिया इस कारण वे जब भी सामने आते दिखते प्रोफेसर धीरे से बोलते हैं, साला टालू मिक्सचर आ रहा है। (जैसे ही वह पास आते वे कहने लगते, अरे काम करने की शैली हो तो बड़े बाबू जैसी इनके मुकाबले कोई काम करने की सानी नहीं है। जब भी किसी काम की अर्जेंसी रहती, पानी सर से ऊपर बहता है, तब वे फाइल में इसी मक्खी बिठाते कि उस पर क्वेरी, जांच बैठ जाती है और फाइल वापस टालू मिक्सचर वाले बड़े बाबू की टेबल पर आ टपकती।

वे बोले टालमटोल करने का प्रमुख केंद्र सरकारी कार्यालय होते हैं, जहां पर टालमटोल करने की एक टेबल होती है जिसमें खाने और अंदरखाने होते हैं। यह टेबल चिरंजीवी होती है उसके ऊपर से फाइलों का अंबार कभी खत्म नहीं होता। टालमटोल केंद्र की इस कुर्सी पर बड़े बाबू बैठते हैं जिनके डीएनए में टालमटोल ही भरा पड़ा है। वे टालने के भाव से महत्वपूर्ण कार्य को भी क्वेरी की क्यारी में डाल देते हैं। टालमटोल करने की प्रवृत्ति में जांच कमेटी और कोई बड़ी नीति या प्रोजेक्ट के लिए किसी जांच आयोग को गठित करना टालमटोल के महत्वपूर्ण अस्त्र है यह अस्त्र सरकारी नीतियों में रोड़ा अटकाने के लिए कारगर होते हैं। इस पर रामेश्वरम जी बोले, कई लोगों की हैबिट ही टालमटोल की रहती है। किसी भी कामकाज को वे टरकाने, टालने, ना नुकूर करने से बाज नहीं आते हैं। कई टालमटोल करने वाले बहाना बनाने में मास्टर डिग्री धारी होते हैं, कई तो अगर, मगर बोलकर काम को टाल जाते हैं। कई हिले हवाले के हवाले काम सुपुर्द कर काम को टालमटोल का टूल बना देते है।

इस पर रमेश बाबू बोले, टालमटोल एक मुहावरा है। टालमटोल करने वालों को कुदरत ने अनसुना करने का बड़ा गुण दिया है। यह अनसुना करना ही उनका बड़ा अवगुण बन जाता है। और बातें सुनकर भी टालने और टरकाना, आनाकानी करने से टालमटोल करने वाले टालू मिक्सचर की ग्रेड में आ जाते हैं।

विश्व हाथी दिवस पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

लेखक पत्रकार हैं।

अंतिम दर्शन के कगार पर पहुंचते हाथी

कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हम हाथियों के पारंपरिक आवासों पर लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं और मानवजनित दबाव के कारण हाथियों को उनके आवासों से बाहर खदेड़ा जा रहा है। हाथियों के चरने के क्षेत्र में पशुओं के चरने और औद्योगिक विकास का दबाव निरंतर बढ़ रहा है, जिससे हाथियों के लिए उपलब्ध भोजन की मात्रा प्रभावित हो रही है और भूख से व्याकुल घबराए हुए हाथियों द्वारा आसपास के लोगों पर हमला किए जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। विशालकाय जंगलों में घूमने वाले हाथियों के पास अलग-थलग पड़ी जमीन के छोटे-छोटे हिस्से ही रह जाने के कारण जब जंगलों को कब्जाकर बनी बस्तियों में हाथियों का आक्रमण होता है तो वहां भूखे हाथी एक ही रात में पूरे एक साल की फसल नष्ट कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आजीविका के लिए फसलों पर ही निर्भर रहने वाले समुदायों में आक्रोश पनपता है, जिसकी परिणति मानव और हाथी संघर्ष के रूप में होती है। इस संघर्ष में दोनों या तो घायल होते हैं या मारे जाते हैं।

हाथी धरती पर सबसे बड़ा जमीनी जानवर हैं, जो झुंड में रहने वाले बुद्धिमान सामाजिक प्राणी हैं। दुनियाभर की विभिन्न संस्कृतियों में हाथी को प्यार, सम्मान और आदर दिया जाता रहा है लेकिन फिर भी यह चिंता का बड़ा कारण है कि दो विशाल महाद्वीपों एशिया तथा अफ्रीका में धरती का यह शानदार प्राणी अंतिम दर्शन के कगार पर हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार पिछले एक दशक में ही हाथियों की संख्या में करीब 62 प्रतिशत की गिरावट आई है और हाथियों के संरक्षण के लिए यदि तत्काल सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए तो अगले दशक के अंत तक अधिकांश हाथी समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की गंभीर दुर्दशा की ओर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष एक विशेष थीम के साथ 12 अगस्त को 'विश्व हाथी दिवस' मनाया जाता है। हाथियों के प्राकृतिक आवास खत्म होते जाने से हाथियों के साथ मानव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। इसी संघर्ष के फलस्वरूप हाथियों को पकड़ लिया जाता है या मार दिया जाता है। पकड़े गए ऐसे ही कुछ हाथियों को चिड़ियाघरों तथा सर्कसों में भेज दिया जाता है, जहां वे जीवनभर करतब दिखाने में ही बिता देते हैं।

कृषि और बुनियादी ढ़ांचे के विकास के लिए हम हाथियों के पारंपरिक आवासों पर लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं और मानवजनित दबाव के कारण हाथियों को उनके आवासों से बाहर खदेड़ा जा रहा है। हाथियों के चरने के क्षेत्र में पशुओं के चरने और औद्योगिक विकास का दबाव निरंतर बढ़ रहा है, जिससे हाथियों के लिए उपलब्ध भोजन की मात्रा प्रभावित हो रही है और भूख से व्याकुल घबराए हुए हाथियों द्वारा आसपास के लोगों पर हमला किए जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। विशालकाय जंगलों में घूमने वाले हाथियों के पास अलग-थलग पड़ी जमीन के छोटे-छोटे हिस्से ही रह जाने के कारण जब जंगलों को कब्जाकर बनी बस्तियों में हाथियों का आक्रमण होता है तो वहां भूखे हाथी एक ही रात में पूरे एक साल की फसल नष्ट कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आजीविका के लिए फसलों पर ही निर्भर रहने वाले समुदायों में आक्रोश पनपता है, जिसकी परिणति मानव और हाथी संघर्ष के रूप में होती है। इस संघर्ष में दोनों या तो घायल होते हैं या मारे जाते हैं।

विभिन्न शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि मानव बस्तियां और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न जैविक दबाव तथा सड़कें, रेलवे लाइन, नहरें और गलियारे वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण इत्यादि रैखिक अवसंरचनाएं मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश के प्रमुख कारण हैं। सड़कें, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, कारखाने और मानव बस्तियां वन्यजीवों की आवाजाही में बाधा बन रही हैं, जिससे उनके प्राकृतिक आवास छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो रहे हैं। वन्यजीवों के अलग-थलग आवास के इन द्वीपों को जोड़ने के लिए गलियारों के बिना, झुंडों को भोजन और पानी तक पहुंचने में परेशानी होती है और वे अपने हमवतन लोगों से भी अलग हो जाते हैं, जिससे उनके सामाजिककरण और प्रजनन के अवसर भी कम हो रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार एशिया और अफ्रीका में यह सब हाथियों के अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। एशियाई हाथियों की वैश्विक आबादी का 60 प्रतिशत से अधिक भारत में है। वर्तमान में देश के 14 राज्यों में 65 हजार वर्ग किलोमीटर में हाथियों के लिए 30 वन क्षेत्र सुरक्षित हैं लेकिन भारत में भी अब एक ओर जहां हर साल 100 से भी ज्यादा हाथी मानव-हाथी संघर्ष के कारण जान से मार दिए जाते हैं, वहीं प्रतिदिन औसतन एक व्यक्ति भी इस संघर्ष में मारा जाता है। पिछले छह वर्षों में मानव-हाथी संघर्ष के कारण हुई कुल मौतों में से 48 प्रतिशत ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में हुई जबकि इन तीन राज्यों और असम, छत्तीसगढ़ तथा तमिलनाडु सहित कुल छह राज्यों में यह संख्या कुल मौतों का 85 प्रतिशत है।

हाथियों की संख्या में गिरावट के प्रमुख कारणों में आवास की क्षति के अलावा मानव-हाथी संघर्ष, उनके साथ कैद में दुर्व्यवहार और अवैध शिकार शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार हाथी दांत, मांस और शरीर के अंगों की तलाश में शिकारियों द्वारा प्रतिदिन करीब सौ अफ्रीकी हाथियों को मार दिया जाता है। चीन में हाथी दांत की कीमतें कई गुना बढ़ जाने के कारण हाथियों का अवैध शिकार आसमान छूने लगा। एशिया में ही हाथी दांत के लिए हजारों अफ्रीकी हाथियों को मार डाला जाता है। हाथी दांत के लिए अवैध शिकार और चिड़ियाघरों तथा सर्कसों सहित बंदी वन्यजीव उद्योग के लिए जंगली जानवरों को पकड़ने के कारण अफ्रीकी और एशियाई हाथियों को जंगल में खतरा है। जंगली हाथियों का सीमा पार व्यापार भी होता है। भारत से नेपाल में जीवित हाथियों की तस्करी के कुछ मामले सामने भी आ चुके हैं। हालांकि भारत में एशियाई हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची 1 के जानवर के रूप में संरक्षित किया गया है और जंगल में उनकी स्थिति को मजबूत करने तथा अवैध शिकार को रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2010 में उन्हें 'भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु' भी नामित किया जा चुका है। थाईलैंड, भारत, लाओस, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया इत्यादि कई देशों में एक दशक तक किए गए एक अध्ययन के अनुसार पूरे एशिया में इस समय पर्यटकों के मनोरंजन के लिए 357 शिविरों में 3800 से भी ज्यादा हाथी बंदी हैं। इनमें से करीब 2400 हाथी गंभीर रूप से भयावह परिस्थितियों में पीड़ित हैं, जिनमें से केवल 279 हाथियों को ही उच्च कल्याण स्थलों पर रखा गया है। अध्ययन के मुताबिक बंदी हाथियों के साथ प्रायः काफी दुर्व्यवहार किया जाता है, जिनमें से अधिकांश पैर की समस्याओं और आंखों की बीमारियों से पीड़ित हैं। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार देश में करीब 27 हजार जंगली हाथी हैं, जिनमें से 2675 बंदी हाथी हैं। कथित तौर पर इनमें से 1821 हाथी निजी हिरासत में हैं जबकि बाकी विभिन्न राज्यों के वन विभाग की देखरेख में हैं। निजी हिरासत में बंदी हाथियों का स्वामित्व कुछ मंदिरों और प्रभावशाली व्यक्तियों के पास है, जो हाथियों को 'स्टेटस सिंबल' के रूप में रखते हैं।

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि करीबी पर्यटक संपर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी हाथियों को दर्दनाक प्रशिक्षण पद्धति से गुजरना पड़ता है, जिसमें युवा हाथी के बच्चों को उनकी मां से अलग करना, उन्हें अलग-थलग रखना, उन्हें भोजन-पानी से वंचित करना तथा जब तक वे टूट न जाएं और उन्हें डर से नियंत्रित नहीं किया जा सके, इसके लिए उन्हें बार-बार पीटना शामिल हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है अफ्रीकी तथा एशियाई हाथी मानव कैद में रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इनमें से बड़ी संख्या में मानव हिरासत में युवावस्था में ही मर जाते हैं। बहरहाल, विशेषज्ञों के मुताबिक मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और संघर्षरत हाथियों को पकड़ने से रोकने में वन्यजीव गलियारों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

स्वाभिमान, सम्मान और शौर्य का प्रतीक

हर घर तिरंगा

प्रो. रवीन्द्र नाथ तिवारी

लेखक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में प्राचार्य हैं।

स्वतंत्रता के अमृत काल में, भारत सरकार ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 'हर घर तिरंगा' अभियान का आह्वान किया है। यह अभियान केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं, अपितु 13 से 15 अगस्त के मध्य प्रत्येक भारतीय को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी एकता, गौरव और प्रतिबद्धता के प्रकटीकरण का संदेश है। यह अभियान तिरंगे के साथ हमारे रिश्ते को आधिकारिक और संस्थागत दायरे से निकालकर व्यक्तिगत और आत्मिक बनाने का एक सशक्त माध्यम है, जो हमें हमारी सामूहिक पहचान और साझा भविष्य का स्मरण कराता है।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप एक लंबी विकास यात्रा और स्वतंत्रता संग्राम की विविध विचारधाराओं का परिणाम है। इसके मूल डिज़ाइन का श्रेय पिंगली वेंकैया को दिया जाता है, लेकिन इसकी आत्मा दशकों के संघर्ष और बलिदान से बनी है। 1904 में भगिनी निवेदिता ने पहला ध्वज डिजाइन किया, जिसमें लाल और पीली पट्टियाँ थीं–लाल बलिदान और पीला विजय का प्रतीक। केंद्र में 'वज्र' और 'वंदे मातरम' अंकित था। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में हरे, पीले और लाल रंग वाला ध्वज फहराया गया, जिसमें कमल के फूल और 'वंदे मातरम' लिखा था। इससे प्रेरित होकर 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने 'कामा ध्वज' बर्लिन में फहराया, जिसमें केसरिया, पीला और हरा रंग, शीर्ष पर कमल और सप्तर्षि के सात सितारे थे। 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने पाँच लाल और चार हरी पट्टियों वाला ध्वज प्रस्तुत किया, जो हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने गांधीजी को लाल और हरे रंग वाला ध्वज दिखाया। गांधीजी ने सफेद पट्टी और केंद्र में चरखा जोड़ने का सुझाव दिया, जो आत्मनिर्भरता और प्रगति का प्रतीक था। 1931 में ऐतिहासिक सहमति से ध्वज का स्वरूप तय हुआ–केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियाँ, केंद्र में चरखा। केसरिया साहस, सफेद शांति और हरा समृद्धि का प्रतीक बना। अंततः 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र रखा गया, जो राष्ट्र की शाश्वत गति और प्रगति का प्रतीक है। आज यह ध्वज केवल तिरंगा नहीं, अपितु हमारे स्वतंत्रता संग्राम, एकता, अखंडता और राष्ट्र की अनवरत प्रगति की जीवंत पहचान है।

संविधान सभा में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस ध्वज के दार्शनिक महत्व को समझाते हुए कहा था कि केसरिया रंग त्याग और निस्वार्थता का, सफेद रंग प्रकाश, सत्य और सादगी का, तथा हरा रंग धरती और वनस्पति से हमारे संबंध का प्रतीक है, जिस पर हमारा जीवन आधारित है। केंद्र में स्थित अशोक चक्र 'धर्म के शासन' का प्रतिनिधित्व करता है, जो यह संदेश देता है कि इस ध्वज के नीचे शासन करने वालों को सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलना होगा। यह ध्वज केवल कपड़े का

एक टुकड़ा नहीं, अपितु हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, हमारे शहीदों के बलिदान और एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के वादे का जीवंत प्रतीक है। प्रत्येक भारतीय के मन में अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान है। इसी सम्मान को बनाए रखने के लिए भारतीय ध्वज संहिता, 2002 लागू की गई, जो ध्वज फहराने से जुड़े सभी नियमों और औपचारिकताओं को समेकित करती है। समय के साथ इस संहिता में भी बदलाव किए गए ताकि ध्वज की पहुंच जन-जन तक हो सके। 30 दिसंबर, 2021 को संहिता में संशोधन कर पॉलिएस्टर और मशीन से बने झंडों को भी अनुमति दी गई। ध्वज संहिता में एक और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए देश के नागरिकों को अपने घरों पर दिन-रात तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई। यह निर्णय तिरंगे के साथ हमारे रिश्ते को और भी गहरा और व्यक्तिगत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

इसी राष्ट्रीय भावना को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 'हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता : स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग' अभियान शुरू किया है। यह पहल स्वतंत्रता के उत्सव को स्वच्छता और जल संरक्षण के संकल्प से जोड़ते हुए एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की दिशा में समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अभियान तीन चरणों में संचालित हो रहा है–प्रथम चरण (2-8 अगस्त) में देशभक्ति का वातावरण और तिरंगे के प्रति जागरूकता, द्वितीय चरण (9-12 अगस्त) में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित किया जाना एवं तृतीय चरण (13-15 अगस्त) में हर घर, कार्यालय और वाहन पर तिरंगा फहराया जाना है। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के आदर्शों को आत्मसात करता है। गांवों और पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता, जल स्रोतों व अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इसका संदेश स्पष्ट है कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी नहीं, अपितु गंदगी, रोग और जल संकट से मुक्ति भी है। स्थानीय संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी द्वारा इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। 'हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता' अभियान एक सशक्त एकजुटकारी पहल है, जो हमें व्यक्तिगत पहचान की सीमाओं से ऊपर उठाकर एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। तिरंगे को घर-घर फहराना न केवल स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, अपितु एक स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। यह अभियान प्रत्येक नागरिक में माँ भारती की सेवा हेतु समर्पण की भावना जागृत करता है, ताकि हमारा तिरंगा सदैव गर्व और सम्मान के साथ लहराता रहे।

विद्वत्ता -गैर विद्वत्ता विशेषण है, सहजता ही मनुष्यता

दृष्टिकोण

अनिल त्रिवेदी

लेखक अभिभाषक हैं।

विद्वत्ता और गैर विद्वत्ता मनुष्य समाज में पुरातन काल से चली आ रही एक ऐसी अनोखी अहंकार से परिपूर्ण विचार प्रक्रिया है जिसमें उलझा मनुष्य जीवन को चेतना का जीवंत स्वरूप होने के बाद भी अप्राकृतिक जड़ता के स्वरूप में बदल गया है। समूची मानव सभ्यता ने अपनी सोच समझ के मानदंड को मान्यता देकर मनुष्य समाज को हमेशा के लिए विद्वत्ता और गैर विद्वत्ता के दो विशेषणों या मानसिक स्वरूपों में बांट दिया है। विद्वत्ता न तो विचार का सर्वोच्च शिखर है और न ही गैर विद्वत्ता, विचार का पाताल लोक। विचार मूल रूप में विचार ही है मनुष्य विचार को विचार की तरह न लेते हुए कई तरह के विशेषणों में बदलने का आदि हो चुका है तभी तो विचार मनुष्य के मन में अपने आप अपनी मौलिकताओं से विस्थापित होकर विद्वत्ता और गैर विद्वत्ता के दो अप्राकृतिक छोर में बट गया।

पता नहीं मनुष्य का मस्तिष्क सहजता को छोड़कर विद्वत्ता और गैर विद्वत्ता के फेर में क्यों उलझा? सरल सहज मनुष्यता इतने लंबे कालखंड से मनुष्य के मन से निरन्तर क्यों सिकुड़ती जा रही है? क्यों मनुष्य अपनी सहज सरल मनुष्यता को छोड़कर विद्वान बनने के चक्रव्यूह में अपनी गैर विद्वत्ता को जाने अनजाने उजागर करने में ही अपना समूचा जीवन जटिल बना लेता है। प्रकृति कभी कृत्रिम नहीं होती है,सदैव सरल सहज एवं चेतन ही रहती है। प्रकृति के एक अंश वनस्पति जगत का जीवन अंकुरित होने से पुनः बीज बनने तक सदैव एक जैसी सरलतम पर अंतहीन जीवन यात्रा पूरी करते कभी-भी नहीं थकता, प्राणियों में सबसे ज्यादा विकसित होने का दावा करने वाले मनुष्य ने ही विद्वत्ता और गैर विद्वत्ता का द्वंद्व क्यों खड़ा किया? फिर प्रकृति का अंश मनुष्य अपनी समूची जीवन यात्रा में आदि से अंत तक सहज सरल और प्राकृतिक स्वरूप में क्यों नहीं रह पाता है? क्या प्राकृतिक रूप से सदैव सरल सहज रह पाना संभव नहीं है! फिर प्रकृति क्यों सदैव सरल सहज ही रहती है? यह मनुष्य जीवन को लेकर मन में उठा एक यक्ष प्रश्न है कि मनुष्य सदैव सरल सहज मनुष्यता को छोड़कर विद्वान बनने की दौड़ में शामिल होकर अपनी गैर विद्वत्ता को उजागर क्यों करता है? प्रकृति से एकदम अलग मनुष्य मन की प्रकृति में यह द्वैत भाव क्यों है? प्रकृति सदैव सरल सहज स्वरूप में अभिव्यक्त होती है जबकि मनुष्य मन सरलतम स्वरूप से विशिष्टता की ओर गतिशील होता दिखाई देता है। यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य प्रकृति की कृति है और मनुष्य अपनी कृति से अपने जीवन के प्राकृतिक स्वरूप को कुछ हद तक कम या ज्यादा बदल सकता है पर पूरी तरह नहीं बदल सकता। प्रकृति में विशिष्टता, विद्वत्ता और गैर विद्वत्ता का भेद नहीं है प्रकृति सनातन स्वरूप में अभिव्यक्त रहती है जिसमें निरन्तर प्राकृतिक प्रवाह मूल रूप से होता है। उसमें कमी बेशी, बदलाव या ऊंच नीच के भेदभाव किसी भी स्तर पर या रूप में मौजूद नहीं होते।

विद्वत्ता और गैर विद्वत्ता मनुष्य समाज में पुरातन काल से चली आ रही एक ऐसी अनोखी अहंकार से परिपूर्ण विचार प्रक्रिया है जिसमें उलझा मनुष्य जीवन को चेतना का जीवंत स्वरूप होने के बाद भी अप्राकृतिक जड़ता के स्वरूप में बदल गया है। समूची मानव सभ्यता ने अपनी सोच समझ के मानदंड को मान्यता देकर मनुष्य समाज को हमेशा के लिए विद्वत्ता और गैर विद्वत्ता के दो विशेषणों या मानसिक स्वरूपों में बांट दिया है। विद्वत्ता न तो विचार का सर्वोच्च शिखर है और न ही गैर विद्वत्ता, विचार का पाताल लोक। विचार मूल रूप में विचार ही है मनुष्य विचार को विचार की तरह न लेते हुए कई तरह के विशेषणों में बदलने का आदि हो चुका है तभी तो विचार मनुष्य के मन में अपने आप अपनी मौलिकताओं से विस्थापित होकर विद्वत्ता और गैर विद्वत्ता के दो अप्राकृतिक छोर में बट गया । मनुष्य स्वयं ही विचार के विशेषणात्मक बंटवारे के फलस्वरूप एक अंतहीन चक्रव्यूह में उलझ गया। इसीसे मनुष्य अपने जीवन या अन्तर्मन में स्वयं की प्राकृतिक मनुष्यता को अप्राकृतिक जड़ता की ओर तेजी से निरन्तर बढ़ते रहने से रोक नहीं पाता। फलस्वरूप प्राकृतिक सहजता का निरन्तर लोप होता है।इस विरोधाभास के लिए मनुष्य की अप्राकृतिक विशेषणात्मक विचार प्रक्रिया की निरन्तर चाहना ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्या मनुष्य मन या जीवन बिना विशेषण के संभव ही नहीं है? मनुष्य अपने जीवन को जितना अधिक अप्राकृतिक विकास या उन्नति की ओर धकेलने की गति को तेज करता रहेगा उतना मनुष्य का प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तित हो कर कृत्रिम जीवन की और निरन्तर बढ़ेगा। कृत्रिम रूप से मनुष्यों के विकास की अंधी जीवन यात्रा ही मनुष्यों की मनुष्यता के प्राकृतिक स्वरूप को कृत्रिम रूप में निरन्तर बदलती रहती है। शायद इस वजह से ही मनुष्य मन में प्राकृतिक प्रवाह और मनुष्य के कृतित्व की जुगलबंदी के द्वंद्व की अभिव्यक्ति होती दिखाई देती है। प्रकृति और मनुष्य का स्वरूप बूंद और समुद्र जैसा ही है। मनुष्य का स्वरूप साकार और नश्वर है पर प्रकृति निराकार स्वरूप में हर कहीं व्याप्त होकर अविनाशी है। प्रकृति में जीवन मौलिक घटना है। मौलिक विचार को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रकृति का यह प्राकृतिक स्वरूप है कि विचार मनुष्य के मन की आधारभूमि में ही प्रगट होते हैं। मनुष्य के माध्यम से प्रगट विचार भी ऊर्जा का अंतहीन प्रवाह है। जैसे अग्नि भिन्न भिन्न रूप से प्रस्फुटित होकर भी अग्नि ही होती है मात्रा सूक्ष्म या विशाल होती है। हवा मंद हो या आंधी तूफान के रूप में प्रगट हो होती हमेशा हवा ही है। प्रकाश और समय भी सदैव तत्पर रहते हैं। वैसे ही विचार भी मनुष्य मन की अनन्त ऊर्जा का निरन्तर प्रकटीकरण है। मनुष्य मन की आधारभूमि में विचार प्रवाह एक प्राकृतिक अभिव्यक्ति है जो सरलतम सहज जीवन यानी मनुष्यता की जीवन्त एवं अंतहीन अभिव्यक्ति है।

एथेनाल प्लांट खुलने से बढ़ी मक्का की मांग, उत्पादन और भाव बढ़ने से किसानों का बढ़ा रुझान

तीन साल में 28,518 हेक्टेयर बढ़ा मक्का बुआई का रकबा

बैतूल। आदिवासी बाहुल्य जिले में अब किसान मक्का की खेती की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सोयाबीन का घटता उत्पादन, दाम कम होने और जिले में एथेनाल प्लांट खुलने से बढ़ी मांग के चलते किसान मक्का लगा रहे हैं। 3 साल में जिले में खरीफ सीजन में मक्का का रकबा 28518 हेक्टेयर बढ़ा है, जबकि सोयाबीन का रकबा 31494 हेक्टेयर घटा है। फसल के बदलते ट्रेंड के चलते अब किसान बारिश के साथ गर्मी में भी मक्का की बोवनी करने लगे हैं। मक्का की खेती में उत्पादन अधिक होने और दाम बेहतर मिलने से किसान इसकी ओर बढने लगे हैं। वैसे जिले में खरीफ सीजन में सोयाबीन मुख्य फसल मानी जाती थी। जिले के कुल साढ़े 4 लाख हेक्टेयर में से 2023 में 208494 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी होती थी, लेकिन अब यह घटकर इस सीजन में केवल 1 लाख 77 हजार हेक्टेयर रह गई है। वहीं मक्का का रकबा बढक़र 2 लाख 11 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इस सीजन में किसानों ने बारिश होने के पहले से ही मक्का की बोवनी शुरू कर दी थी। सोयाबीन फसल को बारिश व कीट प्रकोप (झल्ली लगने) के कारण किसानों को नुकसान हुआ, वहीं लागत बढ़ी और मंडियों में दाम कम मिलने के कारण किसानों का रुख मक्का फसल की ओर हुआ। क्योंकि यह फसल कम लागत में अच्छी पैदावार देती है।

एक हेक्टेयर में 5 क्विंटल तक घटा सोयाबीन का उत्पादन...

सोयाबीन के उत्पादन में एक हेक्टेयर में 5 क्विंटल तक घटा है। फसल में बीमारियां अधिक लगने लगी है, जिसका पता किसान को डेढ़ माह बाद लगता है। इसके कारण वह बचाव भी नहीं कर पाता है। उत्पादन घटने के साथ दाम भी घट रहे हैं। जबकि मक्का का उत्पादन सोयाबीन से चार गुना अधिक हो गया है। हालांकि मक्का और सोयाबीन में लागत बराबर ही लगती है, लेकिन उत्पादन अधिक होने के कारण किसान मक्का की ओर बढ़ रहे हैं। मक्के की मांग कई कारणों से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या, आहार में बदलाव, और पोल्ट्री, डेयरी, और इथेनॉल जैसे उद्योगों में मक्का का बढ़ता उपयोग इसके मुख्य कारण हैं। जिसके कारण मक्का उत्पादन बढ़ रहा है और मांग बढने से किसानों का कम लागत में बेहतर मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है।

जिले में घट रहा सोयाबीन का रकबा

जिले में सोयाबीन के रकबे में कमी आने की प्रमुख वजह जलवायु परिवर्तन, कीटों का प्रकोप, रोगों का प्रभाव और किसानों के लिए कम आय होना भी है। जिसके कारण किसानों का सोयाबीन फसल से मोहभंग होता जा रहा है। 2023 में जिले में सोयाबीन का रकबा 208494 हेक्टेयर था, वहीं 2024 में घटकर 178011 हेक्टेयर रह गया, जबकि इस वर्ष 2025 में मात्र 177000 हेक्टेयर में ही सोयाबीन की बुआई हुई है। इसके पीछे किसान बताते है कि सोयाबीन की खेती की लागत अधिक होने के कारण किसान इसकी खेती से दूर हो रहे हैं। कई बार जिले में अत्यधिक बारिश के कारण फसल को नुकसान होता है। सोयाबीन की फसल को इल्लियों और अन्य कीटों से नुकसान होता है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है।

किसान दोनों सीजन में कर रहे मक्का की बोवनी

मक्का का जिले में अच्छा उत्पादन होने से किसानों का रूझान मक्का के प्रति बढ़ गया है। यहीं वजह है कि कृषि विभाग ने मक्के का रकबा बढ़ाकर 2 लाख 12 हजार हेक्टेयर कर दिया है। जबकि तीन साल पहले यानि 2023 में मक्के का रकबा मात्र 182717 हेक्टेयर मात्र हुआ करता था, जो अब धीरे-धीरे बढक़र 2025 में 211500 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। किसान बताते है कि जिले में एथेनाल प्लांट खुलने से मक्के की मांग बढ़ गई है। उत्पादन एक हेक्टेयर में 40 क्विंटल से अधिक होता है। मंडी और बाजार में डिमांड बढने से दाम भी अच्छे मिल रहे है। कम बारिश में भी मक्का फसल को नुकसान नहीं होता है। लागत सोयाबीन के बराबर लगती है, लेकिन उत्पादन अधिक होता है।

इनका कहना है -

अतिवृष्टि, कीट व्याधि से सोयाबीन फसल को नुकसान होता है। कई बार किसानों की लागत तक नहीं निकल पाती है। इसलिए किसान अब मक्का बुवाई पर ज्यादा ध्यान देने लगे है। मार्केट में मक्का की डिमांड भी बढ़ रही है। जिसके कारण किसानों का रूझान मक्का की ओर बढ़ रहा है।

- रामवीर सिंह राजपूत, एसडीओ, कृषि विभाग बैतूल

बैतूल बाजार में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया जमकर डांस

बैतूल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को बैतूल बाजार नगर में भाजपा जिलाध्यक्ष की अगुआई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए, देशभक्ति के गीतों और नारों की गूंज के साथ यह यात्रा निकाली गई। रास्ते में यात्रा का स्वागत नागरिकों ने फूल बरसाकर किया। यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, इतना ही नहीं देशभक्ति गीतों पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने तिरंगा लेकर जमकर डांस भी किया। दोपहर को परिषद के सामुदायिक भवन से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में नगर परिषद अध्यक्ष दुर्गावती संजय वर्मा सहित समस्त पार्षद एवं अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। यात्रा में देशभक्ति देश प्रेम से भरे गीत बज रहे थे। हाथों में तिरंगा

लिए भारत माता की जय वन्देमातरम के नारे भी लग रहे थे। इस यात्रा में लोगों में जमकर उत्साह था। भाजपा जिलाध्यक्ष अपने आप को नहीं पाए और तिरंगा लेकर जमकर डांस भी किया। यात्रा का पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत किया साथ ही चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की। इस यात्रा में नगर के समस्त स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः सामुदायिक भवन लौटी जहां यात्रा का समापन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार ने बताया कि देश के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है ,शाहिद हुए सैनिकों और सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 10 अगस्त से 13 अगस्त तक तिरंगा यात्रा चलेगी और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा पहराने का कार्यक्रम चलेगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तह पौधा रोपण भी किया गया। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार, नगर परिषद अध्यक्ष दुर्गावती संजय वर्मा, उपाध्यक्ष सुरेश गायक वाड़, समस्त पार्षद ,सीएमओ विजय तिवारी , एकाउंटेंट जी आर देशमुख, भाजपा नेता नरेंद्र शुक्ला, जितेंद्र वर्मा सहित गणमान्य नागरिक और परिषद के कर्मचारी,एवं समस्त स्कूलों के शिक्षक मौजूद रहे।

फसल बीमा दावा राशि का वितरण कार्यक्रम का आयोजन

बैतूल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले से किया गया। बैतूल जिले में जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार एवं प्रत्येक तहसील स्तर पर तहसीलों में कार्यक्रम किया गया जिसमे वर्ष रबी 2023-24, खरीफ 2024 एवं रबी 2024-25 की फसल

बीमा दावा राशि 41.56 करोड़ रुपये 44773 किसानों के खातो में सिंगल क्लिक के माध्यम वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार, भाजपा युवा मोर्चा बैतूल जिला मंडल अध्यक्ष बब्लू सुखा, वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र सुक्ला, जिला मंत्री कृषि भोला खंडेलवाल, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष जिनेंद्र वर्मा, केवीके एचओडी डॉ. विजय कुमार वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मेघा दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक संजीव कुमार वर्मा, एडीए दीपक सरियाम, एडीए सुरेंद्र पराते, एसएडीओ अलका कोडापे, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से रीजनल मैनेजर त्रयंबकेश्वर तिवारी, जिला प्रबंधक राकेश कुमार बैरवा उपस्थित रहे।

बीजासनी मंदिर में मनाया जाएगा कृष्ण जन्मोत्सव

कृष्ण जन्माष्टमी पर होती है विशेष साजसज्जा

बैतूल। बैतूल गंज स्थित बीजासनी माता मंदिर में आगामी 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जायेगा। इस अवसर पर रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक विशाल भजन संध्या का आयोजन मंदिर समिति द्वारा किया गया है, रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म होगा,

56 भोग मिठाई, 11 किलो माखन मिश्री एवं पंजरी का भोग अर्पण किया जाएगा एवं महाआरती होगी जिसके पश्चात मिठाई, माखन मिश्री, साबूदाना खिचड़ी एवं पंजरी का भोग श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। मंदिर संस्थापक एवं समिति के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर में विशेष साजसज्जा की जाती है तथा सुंदर-सुंदर झांकियां मंदिर समिति के सदस्य मिलकर सजाते हैं। मंदिर समिति की ओर से उन्होंने समस्त धर्मप्रेमियों से इस आयोजन में बढ़ चढक़र शामिल होकर पुण्य लाभ लेने की अपील की है।

आज नपा निकालेगी विशाल तिरंगा यात्रा

बैतूल। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज 12 अगस्त को आठनेर में दोपहर 2 बजे आठनेर में विशाल तिरंगा यात्रा निकलेगी। तिरंगा यात्रा में निकाय क्षेत्र के सभी शासकीय विभाग, स्कूली छात्र-छात्राएं एवं जनप्रतिनिधि गण शामिल होंगे। नगर परिषद की अध्यक्ष सुषमा मनोज जगताप ने बताया कि तिरंगा यात्रा आठनेर नगर के मुख्य मार्गों से होकर स्थानीय पुलिस ग्राउंड पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन किया जाएगा। श्रीमती जगताप ने क्षेत्र के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं माता-बहनों से इस यात्रा को सफल बनाने की अपील की है।

लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें: कलेक्टर

शाहपुर और बैतूल के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित किए जाने के दिए निर्देश

बैतूल। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दिए। उन्होंने बैठक में नामांकन एवं साइकिल वितरण की जनपदवार विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने नामांकन और साइकिल वितरण में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और आठनेर, शाहपुर और बैतूल के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नामांकन और साइकिल वितरण की मॉनिटरिंग में लापरवाही पर जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव संभागायुक्त नर्मदापुरम को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने उद्यानिकी फसलों की गिरदावरी किए जाने की पिछली बैठकों में दिए गए निर्देश के पालन प्रतिवेदन की जानकारी ली। दिए गए निर्देशों का गंभीरता से क्रियान्वयन नहीं करने पर उन्होंने उप संचालक उद्यानिकी

के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिए। समग्र ई केवायसी अभियान की जनपदवार व निकायवार समीक्षा कर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी जनपद सीईओ एवं सीएमओ को ई-केवायसी के शेष लक्ष्य को भी यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शाहपुर एसडीएम को अपने क्षेत्र में समग्र ई केवायसी में प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बैठक में लंबित पेंशन प्रकरणों की भी विभागवार समीक्षा की और संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय जांच एवं न्यायालयीन प्रकरणों के कारण लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पेंशन प्रकरणों के निराकरण में रूचि नहीं लेने वाले संबंधित जिला अधिकारियों को नोटिस भी देने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने वन व्यापवर्तन के लंबित प्रकरणों की भी विभागवार समीक्षा की। उन्होंने प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही करने वाले जिला अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने एवं प्रकरणों को निरस्त किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की भी कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने विभागवार समीक्षा की और संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे जन शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए गुणवत्ता युक्त और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें। राजस्व विभाग अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा कर सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि पटवारियों को फील्ड पर भेजकर शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक समाधान किया जाना सुनिश्चित कराए।

न्यायिक-विभाजन मुद्दे पर छठवें दिन भी डटे तहसीलदार-नायब तहसीलदार

बैतूल। छठवें दिन भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायिक तथा गैर-न्यायिक विभाजन के खिलाफ अपने विरोध पर अडिग हैं। 6 अगस्त से शुरू हुए इस आंदोलन में अधिकारी जिला मुख्यालयों पर उपस्थित रहकर आपदा प्रबंधन को छोडक़र बाकी सभी कामकाज रोक चुके हैं। मध्यप्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ बैतूल ने भी इस आंदोलन को न्यायोचित बताते हुए नैतिक समर्थन दे दिया है। मध्यप्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ बैतूल ने अपने समर्थन पत्र में स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा पूरी तरह न्यायोचित है और संवर्ग हित में उचित है। संघ ने कहा है कि वह तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार संवर्ग के विरोध स्वरूप आंदोलन का नैतिक समर्थन करता है। आंदोलन के छठवें दिन भी अधिकारी अपनी मांगों पर अडिग हैं। केवल बैतूल जिले में ही नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, जाति, आय, निवासी प्रमाणपत्र जैसे हजारों प्रकरण प्रभावित होकर लंबित पड़े हैं। आंदोलन के चलते आमजन को जरूरी सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि अधिकारी इस मुद्दे पर अपने हक और संवर्ग की गरिमा की रक्षा के लिए डटे हुए हैं।

रक्षाबंधन पर प्रताप वार्ड की बेटियों को मिला अनमोल तोहफा

हिमानी और काव्यानी के नाम से जाना जाएगा घर, माता-पिता का सम्मान है बेटियां : अनिल यादव

बैतूल। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लाडो फाउंडेशन ने बेटियों के सम्मान में ऐसी मिसाल पेश की, जिसने पूरे प्रताप वार्ड में गर्व का माहौल बना दिया। 9 साल 9 महीनों से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश देने वाले इस अभियान के तहत प्रताप वार्ड निवासी पिता राधेलाल बनखेडे माता कविता बनखेड़े की बेटी हिमानी और काव्यानी के नाम की नेम प्लेट उनके घर की शान बन गई। अब यह घर पूरे मोहल्ले में हिमानी और काव्यानी के नाम से जाना जाएगा, और बेटियों के सम्मान की यह पहचान समाज के लिए प्रेरणा बनेगी। लाडो फाउंडेशन के संस्थापक अनिल नारायण यादव इस अवसर पर प्रताप वार्ड पहुँचे और स्वयं हिमानी और काव्यानी को उनके नाम की नेम प्लेट भेंट की। उन्होंने इस अभियान को समाज में बेटियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनकी सामाजिक पहचान को सशक्त बनाने का माध्यम बताया।

अभियान की विशेषता यह है कि बेटियों के नाम की नेम प्लेट घर की दीवार पर लगने से परिवार में गर्व और सम्मान की भावना जागृत होती है। अब तक इस अभियान के तहत देशभर में 3000 से अधिक घरों में बेटियों के नाम की नेम प्लेट लग चुकी है। रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर मिला यह तोहफ़ा बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, बल्कि पूरे समाज को बेटियों के महत्व का एहसास भी कराता है। संस्थापक अनिल नारायण यादव ने बताया कि यह अभियान अब विदेश तक पहुंच चुका है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर में बेटी के नाम की पहचान हो, यही इस प्रयास का उद्देश्य है।

राष्ट्रीय ध्वज की आन-बान-शान में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के गीतों और नारों से गूंजा बैतूल

बैतूल। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर की सडक़ों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए, देशभक्ति के गीतों और नारों की गूंज ने वातावरण को देश प्रेम से सराबोर कर दिया। इस भव्य यात्रा में आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगाबाई उईके, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वतीबाई बारस्कर, सुधाकर पवार, आनंद प्रजापति सहित कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, समाजसेवी और बड़ी संख्या में नागरिक उत्साहपूर्वक शामिल हुए। पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत की गई आकर्षक देश भक्ति धुनों ने यात्रा के जोश और उमंग को दोगुना कर दिया। तिरंगा यात्रा पुलिस कंट्रोल रूम से

प्रारंभ होकर नेहरू पार्क, जिला अस्पताल मार्ग, कोठी बाजार पेट्रोल पंप, शिवाजी चौक होते हुए पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पर संपन्न हुई।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान के तहत जिलेभर में विभिन्न देशभक्ति और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों और पंचायतों में भी तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा हैं। उन्होंने जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस अभियान में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक श्री झारिया ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों के बलिदान को नमन करना और नई पीढ़ी में राष्ट्रप्रेम व कर्तव्यनिष्ठा की भावना जागृत करना है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी एकता, बलिदान और गौरव का प्रतीक है, इसे सम्मान और गर्व के साथ लहराना हम सबका कर्तव्य है।

वोट की पवित्रता बचाने के लिए प्रदेशभर में पुतला दहन और रीवा से वोट सत्याग्रह का आगाज : जीतू पटवारी

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट का अधिकार है। यही अधिकार लोकतंत्र की नींव है और इसी से जनता अपने प्रतिनिधि और सरकार चुनती है। जब इस पवित्र अधिकार के साथ छेड़छाड़ होती है, तो यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक आस्था पर सीधा हमला है।

पटवारी ने बताया कि आज देश के लगभग 300 सांसद, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, तमाम विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर वोट चोरी और चुनाव आयोग की पक्षपाती भूमिका के खिलाफ चुनाव आयोग से मिलने गए थे। लेकिन जनता की आवाज उठाने के बजाय, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए सभी सांसदों को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने कहा- राहुल गांधी जी ने बार-बार चुनाव आयोग को सबूत दिए कि वोट की चोरी करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से जनादेश को मैनिपुलेट किया। यह किसी दल की हार-जीत का सवाल नहीं, बल्कि एक वोट - एक अधिकार की पवित्रता को बनाए रखने की लड़ाई है। श्री पटवारी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर उनका रवैया इसी तरह तानाशाहीपूर्ण रहा, तो मध्य प्रदेश की सड़कें जनता के आंदोलन से भर जाएंगी। आज घर-घर यह बात पहुंच चुकी है कि बीजेपी वोट चोरी से चुनाव जीतती है और जनता अब चुप नहीं बैठेगी।

प्रदेश कांग्रेस ने घोषणा की है कि आज और कल पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के पुतला दहन कार्यक्रम होंगे। 12 अगस्त को रीवा से 'वोट सत्याग्रह' की शुरुआत होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, वरिष्ठ नेता, विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य है जनता को जागरूक करना और मध्य प्रदेश में वोट चोरी से बनी सरकार का सच उजागर करना। श्री पटवारी ने अंत में कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ-हानि के लिए नहीं, बल्कि जनता के वोट की पवित्रता को बचाने और संविधान की रक्षा के लिए है।

संक्षिप्त समाचार

टीबी मरीजों को आहार सामग्री बांटी

तिलावद /मैना (निप्र)। रक्षा बंधन पर पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पोषण आहार का वितरण किया गया। हेमंत कुमार महेश्वरी नोटरी एडवोकेट एवं मप्र ग्रामीण बैंक के संदेश वाहक अशोक कलमोदिया ने टीबी मरीज को पोषण आहार वितरित किया। उन्होंने कहा पोषण आहार मिलने पर मरीज का स्वास्थ्य जल्दी ठीक होता है। इस दौरान आशा कार्यकर्ता पवित्रा आशा कार्यकर्ता, राकेश कलमोदिया ग्राम नगर सुरक्षा समिति सदस्य आदि शामिल थे।

ज्योति कलश यात्रा 1 सितंबर से बैतूल में

बैतूल(निप्र)। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ज्योति कलश यात्रा बैतूल जिले में 1 सितंबर को आएगी। गायत्री परिवार ने बताया ज्योति कलश यात्रा अखंड ज्योति एवं माता भगवती देवी शर्मा के दिव्य अवतरण वर्ष 1926 के 100 वर्ष पूर्ण कर शताब्दी वर्ष के रूप में आ रहे 2026 की तैयारी व संदेश देने के लिए आ रही है। यात्रा शाहपुर तहसील में 1 से 3 सितंबर, घोड़ाडोंगरी में 4 से 6 सितंबर, आमला में 7 से 11 सितंबर, बैतूल में 12 से 14 सितंबर, चिचोली में 15 से 16 सितंबर, भीमपुर में 17 से 18 सितंबर, भैंसदेही में 19 से 21 सितंबर, आठनेर में 22 से 24 सितंबर, प्रभातपट्टन में 25 से 27 सितंबर, मुलताई में 28 से 30 सितंबर तक रहेगी। इसके बाद यह यात्रा पांढुर्ना जाएगी।

30 अगस्त तक फसल बीमा करा सकेंगे किसान

सीहोर(निप्र)। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विकास विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा की तिथि बढ़ा दी है। अऋणी किसानों के लिए खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी है तथा ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। जिन किसानों ने बैंकों से केसीसी लिया है और उनका बीमा बैंक द्वारा किया जाता है। अऋणी किसान सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, जन सेवा केंद्र तथा सीएससी ऑनलाइन पर जाकर फसल बीमा करा सकते हैं। ताकि फसल नुकसानी के समय किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकें।

घायल युवकों को कराया भर्ती

सीहोर(निप्र)। हकीमाबाद की घाटी पर दो बाइक आपस में टकराई जिससे दोनों बाइक चालक गंभीर घायल हो गए। शुक्रवार को योगेश मालवीय ग्राम मेना और हरिओम विश्वकर्मा ग्राम टकराई निवासी की बाइक आपस में हक़ीमाबाद घाटी पर टकराई। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से निकल रहे ग्राम कोठरी निवासी राधेश्याम बामनिया ने घायलों को आष्टा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया और उनके परिजनों को सूचना भी दी।

थाने में हर्षोल्लास से मनाया रक्षाबंधन

भैरूंदा(निप्र)। रक्षाबंधन पर भाई-बहन के रिश्ते के साथ महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी देखने को मिली। स्थानीय थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में थाना प्रभारी घनश्याम सिंह दांगी को सब इंस्पेक्टर पूजा सिंह राजपूत ने राखी बांधी। इस अवसर पर मातृशक्ति की महिलाओं ने भी थाना प्रभारी और समस्त पुलिस स्टाफ को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना की। साथ ही क्षेत्र के कुछ स्कूलों की बालिकाओं ने भी पुलिसकर्मियों को राखी बांधते हुए त्योहार की खुशियां साझा कीं।

152 स्कूलों में राजयोग सिखाएंगे, नशा मुक्ति पर करेंगे काम

सीहोर(निप्र)। ब्रह्माकुमारीज सीहोर सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के मौके पर भव्य कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि शैलेन्द्र राय ने कहा, बहनों का रक्षाबंधन मनाने का तरीका अलौकिक है। यहां आकर शांति और ऊर्जा का अद्भुत अनुभव मिला। राय ने बताया, दीदी के साथ मिलकर 152 स्कूलों में बच्चों को राजयोग मेडिटेशन सिखाएंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम भी करेंगे। सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्माकुमारी पंचशीला दीदी ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक अर्थ को समझाया।

केंद्र सरकार ने विधानसभा - लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की, प्रदेश सरकार नगरीय निकाय में लोकतंत्र की हत्या कर रही है : पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव

भोपाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोट चोरी कर लोकतंत्र की नींव को हिलाया, उसी तरह मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार अब नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन कर निकाय स्तर पर लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है ।

उन्होंने कहा कि धारा 43(क) और 43(ए) निर्वाचित पार्षदों को यह अधिकार देती हैं कि वे महापौर और अध्यक्ष की तानाशाही और मनमानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकें। यह प्रावधान लोकतंत्र के लिए 'सुरक्षा कवच' है। लेकिन भाजपा सरकार बार-बार संशोधन करके इस कवच को कमजोर कर रही है ।

लोकतंत्र पर सीधा प्रहार — तथ्य और आरोप

1. साल भर पहले सरकार ने धारा 43(क) में संशोधन कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की न्यूनतम अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी ।

2. अब इसे साढ़े चार साल करने का प्रस्ताव है – यानी लगभग पूरे कार्यकाल में जनता की नाराज़गी बेअसर कर देना ।

3. धारा 43(ए) के तहत अविश्वास पारित होने के बाद केवल 6 माह का कार्यकाल देने का प्रावधान – जवाबदेही को मज़ाक बना देता है ।

4. यह सब भाजपा के भीतर के असंतोष और जनता के गुस्से को दबाने की सोची-समझी चाल है ।

अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश के 16 नगर निगम, 98 नगरपालिका और 264 नगर परिषदों में 80 प्रतिशत महापौर और अध्यक्ष भाजपा या उसके समर्थित हैं। इनकी कार्यशैली से कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के निर्वाचित पार्षद भी असंतुष्ट हैं । नगरीय प्रशासन और आवास विभाग की योजनाओं में जमीनी स्तर पर खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता के प्रतिनिधि इसका विरोध न कर पाएं, इसलिए भाजपा सरकार अविश्वास प्रस्ताव की धाराओं को पंगु बना रही है । अरुण यादव ने कहा कि पार्षद लोकतंत्र का सबसे अहम हिस्सा हैं, क्योंकि वे सीधे जनता से चुने जाते हैं और जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करते हैं । धारा 43(क) और 43(ए) पर हमला, जनता की आवाज़ पर हमला है। यह सिर्फ अधिकारों की छीना-झपटी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हत्या है।÷ प्रदेशभर के पार्षदों का वृहद सम्मेलन बुलाया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर होगी, जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार बचाने के लिए सड़क पर संघर्ष किया जाएगा ।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल से यूएनएफपीए स्टेट हेड श्री जैकब ने की सौजन्य भेंट

परिवार नियोजन, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं पर हुई विस्तृत चर्चा

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल से मंत्रालय भोपाल में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के स्टेट हेड ऑफ़ ऑफिस श्री सुनील थॉमस जैकब ने सौजन्य भेंट की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने संस्थान द्वारा प्रस्तुत अवलोकनों और सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता और जनजागरूकता अभियानों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विमर्श किया।

बैठक में प्रदेश में परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को नियंत्रित करने के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों और प्राप्त अवलोकनों पर विस्तृत चर्चा हुई। श्री जैकब ने यूएनएफपीए की मध्यप्रदेश में प्रगतिरत गतिविधियों, कार्यक्रमों, उनके परिणामों और क्षेत्रीय स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी साझा की।

भोपाल में 1.89 लाख स्मार्ट मीटर लगे

ज्यादा बिल आने की 547 शिकायतें ; अफसर बोले- जांच कराई, सभी गलत निकली

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर कई विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही उन्हें भारी यानी ज्यादा राशि के बिल दिए जा रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच ही बिजली कंपनी के अफसरों ने सोमवार को पहली बार स्मार्ट मीटर के फायदे भी बताए। 2 घंटे के सेमिनार में स्मार्ट मीटर को क्लीन चीट देते हुए अफसरों ने कहा कि सही रीडिंग हो रही है।

डिप्टी चीफ इंजीनियर बीबीएस परिहार ने कहा कि स्मार्ट मीटर के संबंध में सीएम हेल्पलाइन या अन्य माध्यम से मिली कुल 547 शिकायतों की पड़ताल की। किसी में भी अधिक खपत आने की बात सिद्ध नहीं पाई गई है। ज्यादा बिल आने की बात पर उन्होंने कहा कि कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके यहां पुराने मीटर में गड़बड़ हुई थी। उनकी अब सही रीडिंग आ रही हैं। इस दायरे में सभी उपभोक्ता नहीं है। अफसरों ने ये भी कहा-मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत 16 जिलों में कुल 41 लाख 35 हजार 791 स्मार्ट मीटर लगेंगे। इसमें से भोपाल शहर में अल्फनार पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को 2 लाख 34 हजार 530 एवं अपरावा भोपाल स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड को 3 लाख 62 हजार 425 स्मार्ट मीटर लगाने का अनुबंध कंपनी ने किया है। भोपाल में सितंबर-24 से पुराने मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। 11 अगस्त तक की स्थिति में 1 लाख 89 हजार 82 मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से 7372 उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर की सीरिज में चेक मीटर के रूप में सामान्य डिजिटल इनेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए हैं। इनमें से किसी के यहां भी खपत में कोई अंतर नहीं आया है।

स्मार्ट मीटर के संबंध में मिली कुल 547 शिकायतों में से एक भी सही नहीं पाई गई है। इस संबंध में संबंधित से लिखित में भी लिया है।

सामान्य इलेक्ट्रॉनिक मीटर एवं स्मार्ट मीटर में बिजली खपत दर्ज करने का तरीका समान है, लेकिन स्मार्ट मीटर में एडवांस फिचर होने के कारण रिमोटली रीडिंग ली जा रही है। जिसमें मानवीय गलती होना संभव नहीं है। स्मार्ट मीटर सेल प्रभारी सीके पंवार ने कहा, यदि उपभोक्ता को लगता है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद ज्यादा राशि के बिल आ रहे हैं तो शिकायत करें।

आदिवासी समाज ने बड़ा देव पूजन कर निकाली शोभायात्रा, घोड़े पर बैठ कर चले युवक-युवती

पिपरिया(निप्र)। पिपरिया में शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। दोपहर में कृषि उपज मंडी प्रांगण में आदिवासी समाज ने अपने देवता बड़ा देव का पूजन-अर्चन किया। कृषि मंडी में आयोजित समारोह में आदिवासी समाज के गणमान्य प्रतिनिधियों ने संबोधन दिया। उन्होंने सामाजिक एकता पर जोर दिया। शिक्षा के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बताई। साथ ही नशे से दूर रहने का आग्रह किया। परिवार के विकास पर ध्यान देने का आवाहन भी किया। शाम को कृषि मंडी से शोभायात्रा निकाली गई। इसमें दो महिला और पुरुष घुड़सवार आगे चल रहे थे। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं सजी थीं। सिर पर साफा बांधे पुरुष शान से चल रहे थे। हथवास चौराहे पर शोभायात्रा का स्वागत हुआ। शोभायात्रा शोभापुर रोड होकर मंगलवारा चौक पहुंची। विभिन्न पारंपरिक आदिवासी नृत्य टोलियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने समाज को शुभकामनाएं दीं। शोभायात्रा ओवर ब्रिज, इतवारा बाजार और पचमढ़ी रोड होते हुए गार्डन में समाप्त हुई। इस अवसर पर नगर को झंडे, बैनर और पोस्टर से सजाया गया था। सिटी थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी ने व्यवस्था संभाली। स्टेशन रोड थाना प्रभारी आदित्य सैन और एसडीओपी मोहित यादव के निर्देशन में पुलिस स्टाफ शोभायात्रा की व्यवस्था में लगा रहा।

श्रीकृष्ण का जन्म मनुष्य के उद्धार के लिए हुआ

सीहोर(निप्र)। श्रीकृष्ण का जन्म मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए हुआ है। कंस ने उनके जन्म लेने को रोकने के लिए अथक प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंत में अपने पापों का घड़ा भरने पर श्रीकृष्ण के हाथों मरकर मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने बताया मनुष्य जीवन सबसे उत्तम माना जाता है। इसी योनी में भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं। जिससे वे अपने आराध्य ईश्वर की भक्ति कर सके। श्रीकृष्ण ने भागवत गीता के माध्यम से बुराई व सदाचार के बीच अंतर बताया। ईश्वर को धन दौलत व यज्ञों से कोई सरोकार नहीं है। वह तो केवल स्वच्छ मन से की गई आराधना के अधीन होता है। उक्त विचार शहर के बस स्टैंड पर जारी सात दिवसीय भागवत कथा के अंतिम दिवस पर कथा वाचक पंडित चेतन उपाध्याय ने कहे। इस मौके पर मंच से अनेक श्रद्धालुओं और कथा के आयोजनकर्ताओं का सम्मान करते हुए कहा कि जीवन में भगवान के नाम के जप का मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। कर्म के साथ पुण्य और धर्म का लाभ लेते रहना चाहिए। महत्व जनने के बाद ही श्रद्धा जागती है उन्होंने कहा कि भगवान जात, पात व धर्म नहीं जानते। वह तो भक्ति मात्र के प्रेम को जानते हैं। हर प्रकार के युगों से श्रद्धालुओं को अवगत कराया। समय-समय पर भगवान को भी अपने भक्त की भक्ति के आगे झुककर सहायता के लिए आना पड़ा है। मित्रता, सदाचार, गुण, अवगुण, द्वेष सभी प्रकार के भावों को व्यक्त किया है। जब तक हम किसी चीज के महत्व को नहीं जानते तब तक उसके प्रति मन में श्रद्धा नहीं जगती। कहा कि जब तक भक्तों का मन पवित्र नहीं होगा तब तक भागवत कथा श्रवण का लाभ नहीं मिल सकता।

सीहोर में सूखने लगी सोयाबीन की फसल:किसानों ने खेतों में प्रदर्शन कर सरकार से मुआवजे मांगा

सीहोर(निप्र)। सीहोर में एक सप्ताह से वर्षा की कमी के कारण सोयाबीन की फसल खराब होने लगी है। इससे परेशान किसानों ने खेतों में खड़े होकर प्रदर्शन किया है। किसानों ने सरकार से फसल का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के क्षेत्र इछावर में सोयाबीन की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। इछावर के ग्राम खेरी में किसानों ने अपने खेतों में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों ने अभी तक खेतों का निरीक्षण नहीं किया है। आंकड़ों के अनुसार, सीहोर जिले में अब तक 647 एमएम बारिश हुई है। पिछले साल इसी अवधि में 748 एमएम बारिश दर्ज की गई थी। इछावर क्षेत्र में इस साल अभी तक 614 एमएम बारिश हुई है। जबकि पिछले साल इसी समय 964 एमएम बारिश दर्ज की गई थी।

इटारसी में दस दिन से नहीं हुई बारिश:1 जून से अब तक 31 इंच पानी गिरा, 13 अगस्त से हो सकती है बारिश

इटारसी (निप्र)। इटारसी में पिछले एक हफ्ते से शहर में बारिश रुकी हुई है। इससे खेतों में लगी धान की फसल प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग कहना है कि 13 अगस्त से फिर जिले में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से बारिश थमने के साथ ही मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। तेज धूप से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक जून से अब तक 786 मिली मीटर यानि 31 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल 34 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी थी। हालांकि पिछले अगस्त माह में हुई जोरदार बारिश से तवा पूरा भर गया है। डैम को जलस्तर 1160.20 फीट पर बताया जा रहा है।

अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना : जिले में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी और लगे हुए पश्चिमी-मध्य में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस कारण नर्मदापुरम जिले में 13 अगस्त के आसपास अच्छी बारिश अधिकतर इलाकों में हो सकती है। वर्तमान में मानसून टर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से होकर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बनी है। एक चक्रवातीय परिसंचरण यूपी की ओर बना है। इसके प्रभाव से नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी।

31 डिग्री पहुंचा क्षेत्र का तापमान : शनिवार को दिन का तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25. 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को दिन का तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार को 34.8 डिग्री सेल्सियस दिल का तापमान और रात का तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश रुकने के बाद तापमान में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है।

मंत्री ने सदन में दिखाया आईना, मंत्री मौन

स्क्रैप में कमीशन का खेला

प्रदेश के एक भारी भरकम विभाग महिला एवं बाल विकास में कबाड़ वाहनों के स्क्रैप के निष्पादन में हुये खेला की उच्च स्तर तक शिकायत हो गई है। विभाग

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

के अधिकारियों ने कमीशन के लिये कबाड़ वाहनों के स्क्रैप का ठेका अपने चहेते ठेकेदार को दिया है। जिसको इस कार्य के अनुभव को लेकर अंगुलियां उठाई जा रही है। इस में भारत सरकार की गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया है। सूत्र बताते हैं कि कबाड़ सैकड़ों वाहनों के ठेका खेला की शिकायत एसोसिएशन के माध्यम से PMO तक पहुंच गई है और अधिकारी अब सन्नाटे में है। देखना है शिकायत क्या रंग लाती है ?

बगल में विराजमान मंत्री मौन

राज्य विधानसभा के पावस सत्र के दौरान एक वरिष्ठ मंत्री ने अपने ही कद्दावर मंत्री साथी को आइना दिखा दिया। हुआ यह कि विधानसभा में गिरते भू जल स्तर को लेकर सदन में चर्चा चल रही थी। मंत्री इसका जवाब दे रहे थे। इस दौरान वरिष्ठ मंत्री ने एक ही समय में लाखों की संख्या में पौधे रोपे जाने की परंपरा पर असहमति जताते हुए कहा कि मैं, इससे सहमत नहीं हूं। इतनी बड़ी संख्या में पौधे रोपे जाने और फिर उनकी उचित देखभाल में भारी परेशानी होती है। हैरानी की बात यह है कि वरिष्ठ मंत्री ने यह बात एसे वक्त कही जब उनके करीब में बैठे साथी कद्दावर मंत्री ने हाल ही में लाखों पौधारोपण कर रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया है। कद्दावर मंत्री ने अपने ही वरिष्ठ साथी मंत्री की बात सुनकर सदन में मौन ही रहना उचित समझा। बता दें कि दोनों वरिष्ठ मंत्री सदन में अगल बगल विराजमान रहते हैं।

वीडियो हो रहे वायरल

वैसे तो राजनेता हो या मंत्री उनके कार्यक्रमों के वीडियो का व्यापक प्रचार प्रसार हो यह उनकी मनसा रहती है, लेकिन इन दिनों राजधानी में एक मंत्री के कई वीडियो रील्स सामने आ रही है और मंत्री जी इससे हैरान व नाराज हैं। मंत्री की वीडियो रील्स उनके स्थानीय विरोधी ही जारी कर रहे हैं। इन वीडियो रील्स को जारी करने का उनका क्या मकसद है यह तो वही जाने, लेकिन यह वीडियो रील्स कहीं मंत्री जी के लिए आफत ना बन जाए। आपको बता दें कि इन वीडियो रील्स में हाल ही में पुलिस के हफ्ते चढ़े एमडी ड्रग्स माफिया सरगना के साथ मंत्री जी है और मंत्री जी सरगना के परिवार के साथ खुशनुमा माहौल में दिख रहे है।

विधायकों ने बांधे तारीफ के पुल

रविवार को राजधानी के सबसे व्यस्ततम मार्ग पर दो विधायकों का आमना सामना हो गया और दोनों एक दूसरे की तारीफ किए बिना नहीं रहे। युवा विधायक ने तो वरिष्ठ विधायक की सक्रियता और युवा देखने की ललक को जमकर तारीफ की वहीं वरिष्ठ विधायक भी का पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने ही युवा विधायक साथी की संगठन और कर्तव्य के प्रति लगन की जमकर तारीफ की। दोनों विधायक एक दूसरे से गले भी मिले। इस दौरान व्यस्ततम मार्ग पर दोनों विधायकों के समर्थकों ने बातचीत का लुप्त उठाया। वरिष्ठ विधायक सुरेंद्र पटवा हैं तो युवा विधायक भगवान दास सबनानी। सबनानी जी तिरंगा यात्रा के लिए मार्ग का निरीक्षण कर रहे थे तो मंत्रालय के पास दोनों विधायक एक दूसरे के आमने-सामने हो गए।

सीएम ने बनाया रिकॉर्ड

कृषि के क्षेत्र में कई अवार्ड अर्जित करने वाली राज्य की भाजपा सरकार ने एक और नया रिकॉर्ड दर्ज कराया है। नया रिकॉर्ड मुख्यमंत्री मोहन यादव की कप्तानी में दर्ज हुआ है। रिकॉर्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश बनने के बाद वर्ष 2003 तक प्रदेश में सिंचाई का जितना रकबा था उतना रकबा तो वर्तमान मुख्यमंत्री के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने निर्मित कर लिया है। यानी की मुख्यमंत्री यादव के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में सवा सात लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र मध्य प्रदेश में और बढ़ गया। मुख्यमंत्री यादव के कुशल नेतृत्व में इसी तरह मध्य प्रदेश का सिंचाई रकबा बढ़ता रहा तो मौजूदा सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल में बढे सिंचाई के रकाबे को कई गुना पीछा छोड़ देंगे।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विदिशा के देहदानी समाजसेवी अरविंद कुमार जैन को दी श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने विदिशा के देहदानी समाजसेवी दिवंगत श्री अरविंद कुमार जैन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि 'अंगदान, जीवनदान है' और श्री जैन का यह अमूल्य योगदान सम्पूर्ण समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। श्री जैन का शनिवार को भोपाल के सेज अपोलो अस्पताल में उपचार के दौरान

निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह एंबुलेंस द्वारा विदिशा मेडिकल कॉलेज पहुंचाई गई, जहां राजकीय सम्मान के साथ 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उल्लेखनीय है कि मूलतः विदिशा निवासी श्री जैन पिछले चार दशकों से सिरोंज में रह रहे थे। वे सामाजिक, धार्मिक व मानवीय कार्यों में निरंतर सक्रिय रहे। इसके अलावा वे योग क्लब के प्रारंभिक सदस्यों में शामिल थे और स्वस्थ जीवनशैली के समर्थक थे। उन्होंने 22 अक्टूबर 2017 को सार्वजनिक कार्यक्रम में देहदान की शपथ ली थी। इस अवसर पर उनकी पत्नी श्रीमती शाशि जैन और पुत्र श्री अंशुल जैन ने भी देहदान की वसीयत लिखी थी।

ट्रेन में चढ़ गई मानसिक रूप से कमजोर युवती

भोपाल (नप्र)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) भोपाल ने मानसिक रूप से कमजोर एक युवती को सुरक्षित उसके परिजनों के हवाले किया। घटना रविवार को गाड़ी संख्या 20912 के भोपाल स्टेशन आगमन के दौरान हुई। कंट्रोल ऑफिस भोपाल को सूचना मिली थी कि ट्रेन में एक युवती यात्रा कर रही है, जो मानिसक रूप से कमजोर है।

ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही आरपीएफ आरक्षक सत्येंद्र कुमार ने टीटीई शिवकुमार के सहयोग से युवती को सुरक्षित उतारा और आरपीएफ पोस्ट भोपाल लाए। वहां महिला आरक्षक शीतल खन्ना की मौजूदगी में पूछताछ हुई।

युवती की मांग को थाने बुलाकर सौंपा

युवती ने अपना नाम नेहा पुत्री जितेंद्र कुमार निवासी भोपाल बताया। इसके बाद उसकी मां हेमा पत्नी जितेंद्र कुमार को थाने बुलाया गया। पहचान सत्यापित होने के बाद उपनिरीक्षक संध्या चौधरी की देखरेख में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर युवती को सुरक्षित माता के सुपुर्द किया गया।

आरपीएफ ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और मानव सेवा के लिए बल हर समय तत्पर है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि रेलवे सुरक्षा बल केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद में भी अग्रणी है।

पीसीसी के सामने कांग्रेस ने जलाया पुतला

भोपाल (नप्र)। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मार्च निकालने के दौरान उन्हें हिरासत में लेने के विरोध में आज भोपाल में प्रदर्शन किया गया। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर कहा है कि भाजपा चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। आज का दिन इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा।

नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह वोट चोरी का खुलासा किया है, वह भाजपा की असलियत को सामने लाता है। लोकतंत्र की रक्षा और राहुल गांधी की ताकत को बढ़ाने के लिए देश को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। सिंघार ने कहा कि वे राहुल गांधी की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं।

पीसीसी के बाहर जलाया पुतला

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में आज भोपाल में पीसीसी के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुतला जलाया। इस दौरान कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, भोपाल जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, अभिनव बारोलिया समेत अन्य प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

20 साल के बी.टेक छात्र ने किया सुसाइड

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अयोध्या नगर के नरेला शंकरी में रहने वाले बी.टेक छात्र ने सोमवार की दोपहर को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजन द्वारा कई कॉल करने पर भी जब उसने कॉल नहीं उठाया तो दोस्तों को उसके कमरे पर भेजा गया था। जहां गेट अंदर से बंद मिला, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में गेट तोड़कर बॉडी को बरामद किया गया। पीएम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया है।

मेधावी विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए तत्पर है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर 1 लाख 52 हजार रूपय हो गई है, जो वर्ष 2002-03 तक मात्र 11 हजार रुपए थी। पिछले डेढ़ साल में सिंचाई का रकबा साढ़े सात लाख हेक्टेयर बढ़ा है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से प्रदेश के कई जिलों को लाभ होगा।

प्रदेश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार तत्परता पूर्वक हर संभव प्रयास कर रही है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने और शाला में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एक निजी न्यूज चैनल द्वारा आयोजित स्वर्ण शारदा

स्कॉलरशिप-2025 वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिभाशाली छात्राओं को छात्रवृत्ति और प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में प्रथम आने वाली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमरपाटन की कुमारी प्रियल द्विवेदी ने बताया कि वह आगे की पढ़ाई वेल्होर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) में करने की इच्छुक हैं, परंतु परिस्थिति वश यह संभव नहीं हो पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुमारी प्रियल द्विवेदी की वीआईटी में पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में 66 छात्राओं को सम्मानित किया, जिसमें प्रत्येक जिले की टॉपर छात्राओं को 50 हजार रुपए, प्रशस्ति-पत्र और प्रदेश में प्रथम आने वाली कु. प्रियल द्विवेदी को एक लाख रुपए तथा उनके स्कूल को भी एक लाख रुपए की राशि का चैक प्रदान किया।

घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन

भोपाल में युवक की मौत के बाद भी हादसे का खतरा, रहवासी बाले-दहशत में जी रहे दर्जनों परिवार

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गांधी नगर के अर्जुन वार्ड में रहने वाली बहन निधि के जिस घर में भाई सुभाष सेन की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हुई। वहां मीडिया की टीम पहुंची। गांधी नगर थाने के ठीक बगल से गुजरने वाली सड़क पर करीब आधा किलो मीटर चलने के बाद निधि का ससुराल मुख्य मार्ग के करीब चालीस फीट की दूरी पर है। यहां निधि पति विक्की के साथ रहती है। इसी मकान में उसकी दो ननद भी रहती हैं। नीले रंग के इस मकान की छत हाई टेंशन लाइन गुजर रही है।

छत और लाइन के बीच दो फीट का भी फासला नहीं है। कोई छोटा बच्चा भी इसे आसानी से छू सकता है। यह हाल केवल निधि के घर का नहीं, आस पड़ोस के करीब एक दर्जन से अधिक मकानों का है।

निधि की ननद मुस्कान सेन बताती हैं कि हवा के हलके से झोंके से भी हाईटेंशन लाइन छत के छज्जे को छू लेती है। परिवार में छोटे बच्चे हैं, हर समय दहशत रहती है कि कब इस लाइन के कारण कोई हादसा हो जाए। पूर्व में मोहल्ले का एक बच्चा

सुभाष सेन, मृतक — तारा बाई, दादी

हाईटेंशन की चपेट में आ चुका है, इससे उसका हाथ झुलस गया था।

शिफ्टिंग चार्ज के नाम पर डेढ़ लाख रुपए की मांग

विक्की की छोटी बहन ने बताया कि लंबे समय से शिकायतें की जा रही है। लगातार बिजली विभाग को हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करने के लिए गुहार लगाई जा रही है। लेकिन उनकी ओर से लाइन की शिफ्टिंग चार्ज के नाम पर डेढ़ लाख रुपए की मांग की जा रही है।

विभाग वालों का कहना है कि खर्च इससे ज्यादा बड़ सकता है लेकिन कम में काम नहीं हो सकता। हमारा और पड़ोस का परिवार पूर्व में पचास हजार रुपए एकत्र कर विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं कि हम इतने पैसा ही दे सकते हैं, लेकिन डेढ़ लाख से कम में विभाग काम करने को तैयार नहीं हुआ। इसी का नतीजा है कि पूर्व में भाभी निधि करंट की चपेट में आई और उनका हाथ झुलस गया। अब रक्षा बंधन पर आया उनका भाई भी इसी लाइन की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा बैठा।

रहवासी बोले-3 बार कर चुके हैं शिकायत, सुनने को तैयार नहीं

स्थानीय निवासी नासिर ने बताया कि बीते करीब पांच साल में तीन बार अलग-अलग माध्यमों से शिकायतें की जा चुकी हैं। यहां एक नहीं कई हादसे हो चुके हैं। हाल ही में सुभाष की मौत हुई। इससे पहले सुभाष की बहन निधि का हाथ झुलसा गया था। एक पांच साल की मोहल्ले में रहने वाली बच्ची का भी हाथ झुलस चुका है। एक अन्य व्यक्ति की भी हाईटेंशन की चपेट में आने से मौत हो चुकी है।

ग्वालियर-भोपाल संभाग में अब कर्मचारियों में होगी प्रतिस्पर्धा

भोपाल (नप्र)। भोपाल, ग्वालियर संभाग के 16 जिलों में काम करने वाले बिजली कर्मचारियों को अब हर माह 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने संभाग स्तर पर हर माह जोन और वितरण केंद्र में काम करने वाले और बेस्ट परफार्म करने वाले कर्मचारियों की सिलेक्शन प्रोसेस तय करने का फैसला किया है। पुरस्कार के दायरे में कंपनी क्षेत्र में काम करने वाले सभी नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को शामिल किया गया है। यह योजना अगस्त 2025 से शुरू की जा रही है, जो मार्च 2026 तक चलेगी। जिसे जल्द ही कंपनी द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उत्कृष्ट योगदान पर सम्मानित करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब कंपनी द्वारा प्रत्येक माह 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार कंपनी के अंतर्गत संभागीय स्तर पर हर माह जोन एवं वितरण केन्द्र में कार्यरत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीन सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को दिया जाएगा। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया कि इस पुरस्कार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को संतुष्टि के साथ त्वरित और बेहतर सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पहचान दिलाना और अन्य कार्मिकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है।

पांच मापदंडों पर किया जाएगा सिलेक्शन

कंपनी के एमडी सिंघल के अनुसार इस पुरस्कार के लिए कर्मचारियों का चयन कंपनी मुख्यालय द्वारा कंपनी कार्यों के अनुसार निर्धारित पांच मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। इसमें सर्कल कार्यालय द्वारा दो अतिरिक्त मापदंड जोड़े जा सकेंगे। 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' के लिए चयनित कर्मचारियों को न केवल प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा, बल्कि उनका नाम और फोटो भी संभागीय कार्यालयों के साथ-साथ कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में 'वीमेन फॉर ट्रीज' अभियान में 7 हजार स्व सहायता समूहों का योगदान

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ाने के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग केन्द्र सरकार के निर्देश पर 'वीमेर फॉर ट्रीज' अभियान संचालित कर रहा है। पौधरोपण के बाद उनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्व सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपी गयी है। इसके लिये विभाग ने एक करोड़ 14 लाख रूपये की राशि जारी की है।

यह कार्यक्रम 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत लिया गया है। प्रदेश में इस कार्य के लिये 7 हजार स्व सहायता समूहों की महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। 'वीमेर फॉर ट्रीज' में 2 लाख 30 हजार पौधरोपण किया जा चुका है। स्व सहायता समूहों की महिलाएं लगाये गये पौधों के रख-रखाव की जिम्मेदारी आगामी 2 वर्ष तक सुनिश्चित करेंगी। इस कार्यक्रम में स्व सहायता समूहों की महिलाओं के साथ नागरिकों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, नर्सरी स्थापना और मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार किये जा रहे हैं।

पर्यावरण और मातृत्व को समर्पित पहल

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरूआत की गई। यह केवल एक पौधरोपण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मातृत्व के सम्मान और पृथ्वी के संरक्षण की एक भावनात्मक, प्रतिकात्मक और सामाजिक पहल है, जिसमें नागरिक अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाकर प्रकृति से जुड़ते हैं।

अमृत हरित महा अभियान

प्रदेश के 418 नगरीय निकायों में पौधरोपण के लिये 13 जून 2025 से अमृत हरित महा अभियान की शुरूआत की गई। इसके लिये प्रदेश में 2500 नोड़ल कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। अब तक विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा शहरी क्षेत्रों में 41 लाख 65 हजार पौधरोपण किया गया है। इसके साथ ही नगरीय निकायों द्वारा 6 लाख 80 हजार पौधरोपण किया गया है।